राष्ट्रीय मासिक
मूल्य : 40/-

रफ्तार मीडिया

वर्ष : 04 | अंक 32
मई, 2026

SIR का चुनावी नतीजों पर क्या असर?

(294 Seats Analysis)

JHAHIN01072

4 साल बेमिसाल

उत्तराखण्ड में सशक्त भू-कानून

- हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपद को छोड़कर उत्तराखण्ड के अन्य 11 पर्वतीय जिलों में दूसरे राज्यों के लोगों को कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं
- पर्वतीय जिलों में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर लगी रोक
- डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर लगाम, साथ ही देवभूमि की सनातन संस्कृति और पारंपरिक सामाजिक पहचान भी होगी मजबूत

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड | @DIPR_UK | UttarakhandDIPR | www.uttarainformation.gov.in

PAGE 04

रफ्तार मीडिया कवर स्टोरी

प्रबंध संपादक | गौरव कुमार

डिप्टी एडिटर | अरविंद कुमार

संपादकीय कार्यालय
उत्तम निवास, हरमू हाउसिंग कॉलोनी,नियर अरगोड़ा थाना,हरमू,रांची. पिन-834002
ईमेल articleraftaar@gmail.com
विज्ञापन: 9709289751

इंश्योरेंस में 100% FDI

क्या आपको लगता है किसानों का जोखिम सचमुच घटेगा?

भारतीय कृषि आज अनिश्चितताओं के ऐसे दौर से गुजर रही है, जहाँ मौसम, बाजार और लागत - तीनों ही जोखिम को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में फसल बीमा केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं, बल्कि किसानों के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच बन जाता है।

इसी पृष्ठभूमि में इंश्योरेंस सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने का प्रस्ताव एक बड़े सुधार के रूप में सामने आता है। लेकिन यह समझना उतना ही जरूरी है कि यह कदम वास्तविक राहत देगा या केवल संरचनात्मक बदलाव तक सीमित रह जाएगा। सबसे पहले, तथ्य स्पष्ट होना चाहिए - भारत में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 2021 में बढ़ाकर 74% की गई थी। 100% FDI फिलहाल नीति-स्तर पर एक संभावित अगला कदम है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो इसका सबसे तात्कालिक असर पूंजी की उपलब्धता पर पड़ेगा। कृषि बीमा जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में अधिक पूंजी आने से कंपनियां जोखिम उठाने में अधिक सक्षम हो सकती हैं। इससे बीमा कवरेज का विस्तार और नई योजनाओं के विकास की संभावना बढ़ेगी। दूसरा बड़ा बदलाव तकनीकी दक्षता के रूप में सामने आ सकता है। वैश्विक बीमा कंपनियाँ डेटा एनालिटिक्स, सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल जोखिम आकलन और क्लेम प्रोसेसिंग में करती हैं। यदि ये तकनीकें प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो क्लेम आकलन में पारदर्शिता बढ़ सकती है और भुगतान में देरी कम हो सकती है - जो आज भी किसानों की सबसे बड़ी शिकायतों में शामिल है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। विदेशी निवेश के साथ लाभ-केन्द्रित दृष्टिकोण भी मजबूत होता है। कृषि बीमा, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए, कम लाभ वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में यह आशंका बनी रहती है कि कंपनियाँ अपेक्षाकृत लाभदायक क्षेत्रों या फसलों पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि जोखिमपूर्ण इलाकों की उपेक्षा हो। यहीं पर नियामक की भूमिका निर्णायक हो जाती है। भारत की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले से ही सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल पर आधारित है। इसके बावजूद कई राज्यों में क्लेम सेटलमेंट में देरी, प्रीमियम निर्धारण की जटिलता और किसानों की सीमित भागीदारी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इसलिए यह मान लेना कि केवल पूंजी बढ़ने से व्यवस्था स्वतः सुधर जाएगी—एक सरलीकृत निष्कर्ष होगा।

अरविंद कुमार
डिप्टी एडिटर

एक और बड़ी चुनौती बीमा की पहुंच है। देश के करोड़ों छोटे किसान अब भी बीमा दायरे से बाहर हैं। विदेशी निवेश का वास्तविक मूल्य तभी है, जब यह ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच बढ़ाए। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल-आधारित क्लेम प्रणाली और स्थानीय भाषा में जागरूकता अनिवार्य होगी। प्रीमियम की वहनीयता भी एक अहम सवाल है। यदि तकनीकी सुधारों के साथ लागत बढ़ती है और प्रीमियम महंगे होते हैं, तो किसान बीमा से दूर हो सकते हैं। इसलिए सरकार को सब्सिडी और नियमन के माध्यम से संतुलन बनाए रखना होगा, ताकि बीमा सुलभ भी रहे और टिकाऊ भी।

अंततः, 100% FDI को किसी जादुई समाधान के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यह पूंजी, तकनीक और प्रतिस्पर्धा लाने का एक अवसर जरूर है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब नीति का केंद्र किसान होगा, न कि केवल बाजार। मजबूत नियामक ढांचा, पारदर्शी प्रक्रियाएं और जवाबदेही - यही वे तत्व हैं जो इस सुधार को जमीन पर असरदार बना सकते हैं। कृषि में जोखिम समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। बीमा उसी प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।

पिछला अंक

मुद्रक : प्रकाशक एवम स्वतत्वाधिकारी गौरव कुमार के पक्ष में शिवसाई पब्लिकेशन प्रा.लिमिटेड, काठीटांड़,नियर टेंडर बगीचा, एचपी पेट्रोल पंप,पोस्ट एवं थाना रातू। रांची 835222 झारखंड द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार की कैबिनेट का जल्द विस्तार होगा. ये बात नई दिल्ली के एक दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कही. साथ ही राज्य में अब केंद्र की योजनाएं, केंद्रीय नामों से ही लागू की जाएंगी. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे थे. यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात के अलावा अधिकारी ने भाजपा अध्यक्ष,नितिन नवीन, संगठन मंत्री बीएल संतोष और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की. सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार का रोडमैप भी तैयार किया गया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य में उनकी सरकार का कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द होगा. पार्टी अध्यक्ष और केंद्र के बड़े नेताओं से हुई विस्तृत बैठक के बाद रोडमैप तय कर लिया गया है. शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे.

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार बनते ही सभी केंद्रीय योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया गया है. साथ ही एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए उन्होंने कहा कि अब राज्य में सभी केंद्र की योजनाओं को जिसे अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया था उसे लागू किया जाएगा. साथ ही ये भी कहा कि जिन केंद्र की योजनाओं को टीएमसी सरकार नाम बदलकर चला रही थी उन्हें भी उनके ओरिजिनल नाम से लागू किया जाएगा. साथ ही बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार करके और मजबूत टीम के साथ विकास कार्यों को तेज गति दी जाएगी. बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ पर सख्त रुख अपनाया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे लोगों के मुद्दे पर सख्त संकेत देते हुए कहा, "जो भी व्यक्ति अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा. शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं पर बात करते हुय बताया कि, आयुष्मान भारत योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा. नमामि गंगे परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल को पर्याप्त धनराशि और प्रोजेक्ट्स आवंटित किए जाएंगे. कृषि क्षेत्र को विशेष बजट दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि, चिकन नेक क्षेत्र को NHAI को सौंप दिया जाएगा ताकि रणनीतिक महत्व की इस कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके. उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल हर एजेंडे को धरातल पर उतारा जा रहा है और आगे भी पूरा किया जाएगा. ईडी और सीबीआई की भूमिका का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "ईडी और सीबीआई अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रही हैं. उन्होंने कहा कि, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है. भाजपा सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट विस्तार में कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, खासकर उन जिलों से जहां पार्टी को और मजबूती देने की जरूरत है. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल के समग्र विकास रणनीति पर चर्चा हुई. यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं.

"हमारी सरकार बनते ही सभी केंद्रीय योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया गया है. साथ ही एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए उन्होंने कहा कि अब राज्य में सभी केंद्र की योजनाओं को जिसे अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया था उसे लागू किया जाएगा. साथ ही ये भी कहा कि जिन केंद्र की योजनाओं को टीएमसी सरकार नाम बदलकर चला रही थी उन्हें भी उनके ओरिजिनल नाम से लागू किया जाएगा. साथ ही बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार करके और मजबूत टीम के साथ विकास कार्यों को तेज गति दी जाएगी.

'सबका साथ, सबका विकास' के साथ अब होगा 'सबका हिसाब': बंगाल के सीएम की चेतावनी

मुख्यमंत्री बनने के बाद नंदीग्राम के अपने पहले दौरे पर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कानून-व्यवस्था को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया. मंच से विपक्ष और उपद्रवियों को सीधी चेतावनी देते हुए उन्होंने एक नया और आक्रामक नारा दिया. मुख्यमंत्री ने दोटूक शब्दों में कहा, "सबका साथ, सबका विकास तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन इसके साथ ही अब सबका हिसाब भी होगा!" इस दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सख्त सलाह दी और साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले. अपराधियों और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए सीएम ने चेतावनी दी, "उन सभी के लिए एकमात्र जगह जेल है. मैं एक भी अपराधी को नहीं बख्शूंगा और हर एक से पूरी जवाबदेही तय की जाएगी." इस रैली में मुख्यमंत्री ने राज्य में राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुए कार्यकर्ताओं की बात की. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में नंदीग्राम सहित पूरे बंगाल में भाजपा के लगभग 4,500 समर्थकों को झूठे और मनगढ़ंत मामलों में फंसाया गया. मुख्यमंत्री ने देश के कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे इन सभी झूठे मुकदमों से पूरी तरह कानूनी और संवैधानिक तरीकों से निपटेंगे.

शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की बदहाली को लेकर भी तीखे सवाल खड़े किए. उन्होंने बंगाल में माकपा के 34 साल और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से खोखला कर दिया है. राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से बंगाल को जोड़ने का आह्वान करते हुए के सामने 'डबल इंजन सरकार' के विकास मॉडल की उपयोगिता को रखा और साफ किया कि बंगाल में अब तुष्टीकरण की जगह केवल और केवल विकास की राजनीति होगी. हालिया विधानसभा चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही हाई-प्रोफाइल सीटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. संवैधानिक नियमों के तहत उनके स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उपजे असमंजस को दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने मंच से अपने और नंदीग्राम के अटूट रिश्ते को फिर से परिभाषित किया. उन्होंने 2003 के दिनों को याद करते हुए भावुक लहजे में कहा, "आप मुझे बिल्कुल वैसा ही पाएंगे जैसा आप मुझे 2003 से जानते हैं- मैं आपका सगा-संबंधी था, मैं आपका सगा-संबंधी हूं

उन्होंने एलान किया कि नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के सभी स्थानीय और विकास कार्यों का जिम्मा अब कांथी के सांसद सौमेंदु अधिकारी संभालेंगे, जिन्हें स्थानीय भाजपा संगठन का पूरा सहयोग मिलेगा. रविवार की रैली के दौरान नंदीग्राम के शहीद परिवारों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए शुभेंदु ने एक बार फिर भावनात्मक राजनीति को हवा दी. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने सात शहीद परिवारों को मिलने वाला मुआवजा सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि वे उनके राजनीतिक विरोधी थे.

उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग का जिक्र किया. शुभेंदु ने एलान किया, "मोदी जी की मदद से, हमें बंगाल को एक बार फिर 'सोनार बांग्ला' यानी सोने का बंगाल बनाना होगा." इस बयान के जरिए उन्होंने एक बार फिर देश लिए एक सीट छोड़ना अनिवार्य था. भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के समीकरणों को देखते हुए फैसला किया कि शुभेंदु भवानीपुर सीट अपने पास रखेंगे और नंदीग्राम सीट खाली करेंगे. इस फैसले से और हमेशा आपका सगा-संबंधी रहूंगा." नंदीग्राम की जनता को यह महसूस न हो कि उनके विधायक ने उन्हें छोड़ दिया है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक व्यावहारिक प्रशासनिक व्यवस्था की घोषणा की.

बिहार में चल क्या रहा है? नीतीश 'उपमुख्यमंत्री' से रिपोर्ट मांगते हैं

विजय सिन्हा PM से मिलते हैं, सम्राट भी पहुंचे दिल्ली

बिहार की राजनीति इन दिनों कई ऐसे संकेत दे रही है, जिसने सत्ता गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पहुंचते हैं और कैबिनेट की 'एक-एक जानकारी' देने की बात कहते हैं. दूसरी ओर कृषि मंत्री विजय सिन्हा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात होती है, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बिहार NDA में सबकुछ सामान्य है या फिर सत्ता के भीतर कोई नई खींचतान आकार ले रही है? दरअसल, कैबिनेट विस्तार के बाद सभी विभागों में धड़ाधड़ फैसले लिए जाने लगे. सम्राट चौधरी भी कैबिनेट विस्तार से पहले तक फैसलों में कुछ हद तक नीतीश कुमार के साथ कनेक्ट रहते थे, लेकिन जब से कैबिनेट विस्तार हुआ है तब से न तो सम्राट चौधरी और न ही उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री नीतीश से मार्गदर्शन ले रहा है. इसके चलते नीतीश की छटपटाहट बढ़ना लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए काफी संघर्ष किया. हालांकि इसके बाद विजय चौधरी के आवास से नीतीश कुमार निकल गए. कुछ देर बाद ही नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंच गए. जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार करीब 15 मिनट तक रहे. जदयू के कई नेताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक-ठाक है. उसके बाद फिर जदयू कार्यालय से भी निकल गए. वैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास छोड़ चुके हैं और सात सर्कुलर रोड स्थित आवास में अपना नया ठिकाना बनाया है. नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं जिलों का भी दौरा कर रहे

हैं और वहां विकास कार्य की जानकारी ले रहे हैं. ऐसे में सरकार के कामकाज को लेकर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने आज विजय चौधरी से रिपोर्ट देने के लिए कहा उस पर सवाल जरूर उठने लगे हैं. हालांकि भाजपा प्रवक्ता डॉ रामसागर सिंह का कहना है कि बिहार में तो नीतीश कुमार की ही सरकार है उन्होंने ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है. सम्राट चौधरी भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में ही काम कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सरकार के कामकाज को लेकर अपने मंत्रियों से जानना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है. नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसलिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा भी दिलाते रहे हैं कि सरकार सही ढंग से काम कर रही है. नीतीश का अपने मंत्री से कैबिनेट की जानकारी देने को कहना कितना जायज है? क्या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के डिप्टी सीएम से इस तरह का आग्रह कर सकता है कि वह कैबिनेट के भीतर क्या चल रहा उसको अपडेट देता रहे. इसका जवाब विशेषज्ञ देते हैं कि- 'हां ऐसा हो सकता है, क्योंकि पार्टी और सरकार के बीच मंत्री ही होता है जो दोनों को सेतु के तौर पर खड़ा किया जाता है. यह गलत नहीं बल्कि पार्टी का अधिकार भी है क्योंकि पार्टी चुनाव के वक्त जनता से सीधे कनेक्ट होती है और पार्टी को मिले जनाधार के आधार पर ही सरकार का गठन होता है.

विशेषज्ञों का मानना है नीतीश की पार्टी को सरकार के कामकाज की ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के कोटे से डिप्टी सीएम बने विजय चौधरी के आवास पर अचानक पहुंचकर अपनी व्यथा को उनसे कहा होगा. जाते समय भी दोनों नेता नीतीश कुमार और विजय चौधरी इस मुद्दे को रेखांकित करते सुने जा सकते हैं. नीतीश कहते हैं कि "शाम को घर आकर एक-एक चीज बताइएगा कि कैबिनेट में क्या चल रहा है?"

मऊ में गरजे मुख्यमंत्री, बोले - अब बेटियों-व्यापारियों की सुरक्षा में नहीं लगा सकता कोई सेंध

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मऊ में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला. मधुबन के गांधी मैदान में सीएम योगी ने कहा कि याद कीजिए जनपद मऊ की 2005 की तस्वीरें, जब सरकार ने माफिया के सामने मऊ में घुटने टेक दिए थे. सीएम योगी ने कहाकि सड़कों पर चल रही बहन-बेटियों को शोहदे छेड़ते थे, आज उन पर अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है. सीएम ने कहाकि धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डालने वालों को भी सबक सिखाने का काम यूपी सरकार कर रही है. अब कोई बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में नहीं लगा सकता कोई सेंध. सीएम योगी ने कहा कि उस समय रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों तक में बाधाएं खड़ी की जाती थीं और आम जनता भय के माहौल में जीने को मज़बूर थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बहन-बेटियां और व्यापारी शाम होने से पहले घर लौटने को मज़बूर रहते थे. अगर कोई देर हो जाती थी, तो परिवार के लोग चिंता में डूब जाते थे. सड़कों पर शोहदों का आतंक था, लेकिन आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डालने वालों को सबक सिखाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि विकास, विश्वास और सुशासन की नीति पर प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ रही है. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां शीतला देवी धाम, मऊ में 392 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. कार्यक्रम में ऊर्जा

मंत्री ए.के. शर्मा, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, पंचायती राज मंत्री, सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर, विधायक रामविलास चौहान, एमएलसी विजय लाल राजभर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. मऊ के ताजोपुर गांव में शुक्रवार को उस समय ऐतिहासिक माहौल बन गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर पीएन सिंह द्वारा स्थापित 150 बेड के ग्रामीण सैनिक अस्पताल का लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिगेडियर पीएन सिंह ने अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के कई संस्थान स्थापित कर यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण भारत भी आत्मनिर्भरता और विकास का केंद्र बन सकता है. उन्होंने इसे "ग्रामीण स्वावलंबन का अनुपम उदाहरण" बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन जननी और जन्मभूमि का ऋण कभी नहीं चुका सकता. ब्रिगेडियर पीएन सिंह ने अपने गांव में सैनिक आईटीआई, सैनिक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और अब आधुनिक अस्पताल स्थापित कर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण पेश किया है. योगी ने कहा कि यह केवल व्यवसाय नहीं बल्कि राष्ट्रसेवा और समाजसेवा की एक प्रेरणादायी पूजा है. सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "पंचप्रण" का उल्लेख करते हुए कहा कि

विरासत का सम्मान, गुलामी की मानसिकता का त्याग, एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना, सैनिकों का सम्मान और नागरिक कर्तव्यों का पालन—इन सिद्धांतों को यह संस्थान धरातल पर उतार रहा है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब गांव मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे. ताजोपुर जैसे प्रयास पूरे प्रदेश और देश के लिए प्रेरणा बन रहे हैं. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 41 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 83 हो चुकी है.

SIR और जनगणना को लेकर झामुमो का मिशन मोड बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने में जुटी पार्टी!

झारखंड में हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और जनगणना 2027 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब मिशन मोड में नजर आ रहा है. पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक संगठन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुट गई है. इसी कड़ी में झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय राज्यभर में सांगठनिक बैठकों का नेतृत्व कर रहे हैं. जिसमें पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंट (BLA) को SIR की प्रक्रिया और उसके राजनीतिक प्रभावों को लेकर जागरूक किया जा रहा है. 20-21 अप्रैल को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई दो दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया. इस बैठक में SIR और जनगणना जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी और भाजपा के कथित "षड्यंत्र" को विफल करने का संकल्प लिया गया था. तब मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में संगठन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. इसी रणनीति के तहत 25 मई को लोहरदगा और 26 मई को गुमला में जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों और BLA की बड़ी बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में विनोद पांडेय ने कार्यकर्ताओं को SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची के सत्यापन और जनता को जागरूक करने के तौर-तरीकों की विस्तृत जानकारी दी. साथ ही संगठन को और मजबूत बनाने तथा हर बूथ तक पार्टी की

सक्रियता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया. अब पार्टी ने अगले चरण की बैठकों का कार्यक्रम भी तय कर दिया है. 02 जून को पश्चिमी सिंहभूम, 3 जून को पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां, जबकि 4 जून को सिमडेगा में सांगठनिक बैठकें आयोजित होंगी. इन बैठकों में भी जिला से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारी और BLA शामिल होंगे. इस अभियान के जरिए झामुमो भाजपा पर लगातार राजनीतिक हमला भी तेज कर रही है. झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति "पहले अधिकार रोकने, फिर उसी मुद्दे पर राजनीति करने" की रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां राज्य की योजनाओं की राशि रोकी जाती है और फिर विकास नहीं होने का आरोप लगाया जाता है. झामुमो नेता विनोद पांडेय ने बिहार और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि SIR और तकनीकी प्रक्रियाओं की आड़ में गरीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को व्यवस्था से बाहर करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि बिहार में SIR के बाद 35 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, जबकि बंगाल में लाखों लोगों के नाम "Logical Discrepancy" के नाम पर काटे गए.

यह सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकारों पर सुनियोजित हमला है. आज वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, कल राशन रोका जाएगा और परसों कहा जाएगा कि डेटाबेस में आपका अस्तित्व ही नहीं है. झामुमो अब इसी मुद्दे को लेकर गांव-गांव और बूथ-बूथ तक राजनीतिक और सांगठनिक अभियान चलाने की तैयारी में है. जिससे मतदाताओं को जागरूक करने के साथ-साथ पार्टी संगठन को भी जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जा सके.

दुमका में चार दिन में लूट की दूसरी वारदात, आभूषण व्यवसायियों ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में चार दिनों के अंदर लुटेरों ने दो आभूषण व्यवसायियों को निशाना बनाया है. इससे सर्राफा कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत है. बुधवार को सभी व्यापारियों ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से सुरक्षा की गुहार लगाई है. दरअसल, दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कुशबोना गांव में बीती रात एक आभूषण व्यवसायी से ज्वेलरी और नगद रुपयों की लूट हुई है, शिकारीपाड़ा के मुख्य बाजार स्थित आभूषण दुकानदार संजय वर्मा, दुकान बंद करके अपने घर पर्वतपुर गांव जा रहे थे. तभी रास्ते में तीन बाइक पर सवार पांच आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे. पांच आरोपियों में से दो के पास पिस्टल थी. व्यापारी के मुताबिक, पिस्टल को उन्होंने उनकी कनपटी पर सटा दी और उसके पास से आठ हजार रुपये नगद, ढाई सौ ग्राम चांदी के साथ अन्य दुकान की चाबी और कुछ जरूरी कागजात छीन लिए. जाते समय डराने के उद्देश्य से एक राउंड फायरिंग भी की. जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने शिकारीपाड़ा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है.

बता दें कि तीन दिन पहले भी एक आभूषण दुकानदार संतोष वर्मा से इसी तरह लूट का प्रयास किया गया था. इस मामले में शिकारीपाड़ा बाजार के संतोष वर्मा रात में अपनी दुकान बंद करके नजदीक के ही कुम्हारपाड़ा मोहल्ले जा रहे थे. रास्ते में काफी अंधेरा था जबकि तीन अपराधी मौके की फिराक में थे. जैसे ही संतोष वर्मा वहां पहुंचे तीनों व्यापारी झपट पड़े और आभूषण से भरी थैली छीनने लगे लेकिन दुकानदार ने बहादुरी दिखाई और कसकर अपना झोला पकड़कर मदद के लिए आवाज लगाई. उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग एकजुट होने लगे तो खुद को घिरता देख तीनों अपराधी फायरिंग करते भाग निकले. इस मामले में पुलिस की तहकीकात चली रही थी कि बीती रात भी शिकारीपाड़ा में ही दूसरी घटना घट गई. एक सप्ताह में लगातार दो घटनाओं से शिकारीपाड़ा के आभूषण व्यवसायियों में भय है. बुधवार को वे एकजुट होकर शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी से मिले और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की. उधर जिले के खैतान चौक के पास जमनादास बिसेसर लाल ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया. घटना बीती रात कतरास थाना क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक, कतरास थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर घटना घटी. ज्वेलरी शॉप पर करीब 12 लुटेरों ने धावा बोलकर सबसे पहले गार्ड को बंधक बनाया फिर ज्वेलरी शॉप का शटर उखाड़कर जमकर लूट की.

अपराधी कितने की ज्वेलरी अपने साथ ले गए हैं? ये कहना थोड़ा मुश्किल है. पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर 10 से 12 अपराधी नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेटा शहर से बाहर गया हुआ है. बेटे के आने के बाद ही ज्वेलरी चोरी का आंकड़ा मिल पाएगा. बता दें कि तीन दिन पहले भी एक आभूषण दुकानदार संतोष वर्मा से इसी तरह लूट का प्रयास किया गया था. इस मामले में शिकारीपाड़ा बाजार के संतोष वर्मा रात में अपनी दुकान बंद करके नजदीक के ही कुम्हारपाड़ा मोहल्ले जा रहे थे. रास्ते में काफी अंधेरा था जबकि तीन अपराधी मौके की फिराक में थे.

ज्वेलरी शॉप संचालक के पिता ने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा घटना की जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि दुकान उनका बेटा संभालता है. अपराधी दुकान से सोना और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए.

एशियन गेम्स ट्रायल: झारखंड के तीन पहलवान का चयन, पहली बार सीनियर स्तर के ट्रायल में बनाई जगह

झारखंड के खेल इतिहास में गुरुवार को एक नया अध्याय जुड़ गया, जब राज्य के तीन प्रतिभाशाली पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से रवाना हुए. ह पहला अवसर है जब झारखंड से एक साथ तीन पहलवान सीनियर स्तर के एशियन गेम्स ट्रायल के लिए क्वालीफाई करने में सफल हुए हैं. खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से राज्य के खेल जगत में उत्साह और गर्व का माहौल है. एशियन गेम्स ट्रायल के लिए रवाना होने वाले खिलाड़ियों में रिया कुमारी (53 किलोग्राम महिला वर्ग), अमित गोप (77 किलोग्राम ग्रीको रोमन) और अभिषेक कुमार (60 किलोग्राम ग्रीको रोमन) शामिल हैं. रिया और अभिषेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से जुड़े हैं, जबकि अमित गोप रांची से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. तीनों खिलाड़ी दिल्ली और लखनऊ में आयोजित होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेंगे. ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने पर उन्हें एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह मिल सकती है.

बता दें कि एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया में होना है. ऐसे में झारखंड के खिलाड़ियों के पास अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा अवसर होगा. राज्य के खेल प्रेमियों और युवा पहलवानों को इन खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें हैं. झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जताते हुए कहा कि यह झारखंड के लिए ऐतिहासिक क्षण है. हमारे तीनों खिलाड़ियों रिया, अमित और अभिषेक ने अपनी मेहनत और समर्पण के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है. यह सफलता खेल विभाग, झारखंड सरकार, साझा और JSSPS के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है. हमें पूरा विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी ट्रायल में शानदार प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड में कुश्ती के क्षेत्र में लगातार प्रतिभाएं उभर रही हैं और अब राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं. रजनीश कुमार ने यह भी कहा कि रिया, अमित और अभिषेक की सफलता राज्य के हजारों युवा पहलवानों के लिए प्रेरणा बनेगी. खिलाड़ियों के रवाना होने से पहले खेल सचिव मुकेश कुमार, झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष जीशान कमर, खेल निदेशक छवि रंजन, उप निदेशक साझा राजेश कुमार, अभिभावक के. रवि कुमार और मार्गदर्शक भोलानाथ सिंह समेत कई खेल पदाधिकारियों और संघ के सदस्यों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर झारखंड कुश्ती संघ के पदाधिकारी, जिला संघों के प्रतिनिधि, कोच और खिलाड़ियों के परिजन भी मौजूद रहे. सभी ने खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और भारतीय टीम में चयन की कामना की.

झारखंड के तीन पहलवानों का एक साथ एशियन गेम्स ट्रायल तक पहुंचना राज्य में कुश्ती खेल के बढ़ते स्तर और खिलाड़ियों की मेहनत का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है.

झारखंड के लिए एक और गर्व का क्षण सामने आया है. राज्य के उभरते हुए पहलवान अमित गोप का चयन अंडर-23 सीनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता-2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इस वर्ष वियतनाम में आयोजित होने जा रही है, जहां एशिया के कई देशों के बेहतरीन पहलवान अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे. अमित गोप 77 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. अमित गोप की इस उपलब्धि से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है. यह चयन न केवल उनकी व्यक्तिगत मेहनत और लगन का परिणाम है.

तस्करी का नया खेल बिहार में 2.5 करोड़ का गांजा बरामद

कटहल की आड़ में हो रही थी तस्करी

बिहार में पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद सूखे नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में रोहतास पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गांजे की बड़ी खेप को बरामद किया है. जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है. दरअसल जिले के डेहरी में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ओडिशा से एक उजले रंग की पिकअप वैन कटहल लोड कर डेहरी की ओर आ रही है. जिसके नीचे भारी मात्रा में गांजे की खेप छुपा कर रखी गई है. सूचना मिलते ही एएसपी अतुलेश झा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने डेहरी नगर थाना क्षेत्र के पाली मोड़ स्थित जीटी रोड पर सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया. इसी दौरान एक संदिग्ध पिकअप वैन को रोका गया जिस पर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए कटहल लदा हुआ था और तिरपाल से ढका गया था. एएसपी के मुताबिक पुलिस ने जब वाहन की सघन तलाशी ली तो कटहल के नीचे छुपा कर रखे गए लगभग 500 किलोग्राम गांजे की बड़ी खेप को बरामद किया गया.

पुलिस ने मौके से वाहन चालक सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में चालक ने इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के नाम उजागर किए हैं. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है. साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार चालक ने पुलिस को बयान में बताया है कि गांजे की खेप ओडिशा से झारखंड के रास्ते औरंगाबाद होते हुए मोहनिया पहुंचाई जा रही थी. इस मामले में मोहनिया से जुड़े तस्करों की भी पहचान की जा रही है. साथ ही कैमूर पुलिस से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यहां यह बताना भी जरूरी है कि रोहतास जिले का इलाका सूखे नशे के कारोबार के लिए कुख्यात हो चुका है. खासकर डेहरी इलाके में गांजा, हेरोईन की तस्करी में जहां कई युवा संलिप्त हैं वही यह लत युवाओं का भविष्य बिगाड़ रहा है. हालांकि इस मामले में एएसपी अतुलेश झा ने कहा कि सूखे नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है. पुलिस को विभिन्न इलाके में छापेमारी के निर्देश जारी किए गए हैं.

जनसुराज लड़ेगी बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत बोले- BJP को घर में घुसकर हराएंगे

प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि जन सुराज पार्टी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव मैदान में उतरेगी. शिवहर में आयोजित सभा के दौरान पीके ने कहा कि बांकीपुर में पिछले 40-45 वर्षों से एक ही परिवार और भाजपा का दबदबा रहा है, जबकि राजद और कांग्रेस कई बार चुनौती देने के बावजूद सफल नहीं हो सके. उन्होंने दावा किया कि इस बार जन सुराज भाजपा को उसके गढ़ में घुसकर हराएगी और बांकीपुर में सीधी लड़ाई जन सुराज ही देगा. सीधी चुनौती सिर्फ जन सुराज देगा, 40-45 साल से एक ही परिवार जीतता रहा, राजद-कांग्रेस कई बार हारे, जन सुराज इस बार उनके गढ़ में घुसकर भाजपा को हराया जाएगा. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की सबसे चर्चित शहरी विधानसभा सीटों में मानी जाती है.

यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है. यहां से भाजपा नेता नितिन नवीन लगातार कई बार विधायक चुने गए. नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी भाजपा के बड़े नेता रहे थे और बांकीपुर की राजनीति में उनका गहरा प्रभाव था. नितिन नवीन ने पहली बार अपने पिता के निधन के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और फिर लगातार चुनाव जीतते हुए बांकीपुर सीट पर भाजपा की पकड़ मजबूत की. उन्हें संगठन और सरकार दोनों में अहम जिम्मेदारियां मिलती रहीं. भाजपा ने दिसंबर 2025 में नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था. बाद में उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कमान सौंपी गई और वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. इसके बाद मार्च 2026 में भाजपा ने उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजा. राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय नितिन नवीन ने कहा था कि बांकीपुर की जनता के साथ उनका आत्मीय रिश्ता हमेशा बना रहेगा. राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने बांकीपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिसके बाद यहां उपचुनाव की स्थिति बनी. अब इसी सीट पर जन सुराज की एंट्री ने बिहार की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि भाजपा के पारंपरिक गढ़ में पहली बार जनसुराज पार्टी खुली चुनौती देती नजर आ रही है. विधानसभा में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी 342 सीटों में से 338 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. जिसमें कुल 1.6 मिलियन वोट यानी लगभग 16 लाख वोट मिले थे. हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी. अपने पार्टी के प्रदर्शन से सभी लोग दंग थे. ऐसे में एक बार फिर से जन सुराज पार्टी बांकीपुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव के लिए जोर आजमाइश करने की तैयारी कर रही है.

जन सुराज भाजपा को उसके गढ़ में घुसकर हराएगी और बांकीपुर में सीधी लड़ाई जन सुराज ही देगा. सीधी चुनौती सिर्फ जन सुराज देगा, 40-45 साल से एक ही परिवार जीतता रहा, राजद-कांग्रेस कई बार हारे, जन सुराज इस बार उनके गढ़ में घुसकर भाजपा को हराया जाएगा. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की सबसे चर्चित शहरी विधानसभा सीटों में मानी जाती है.

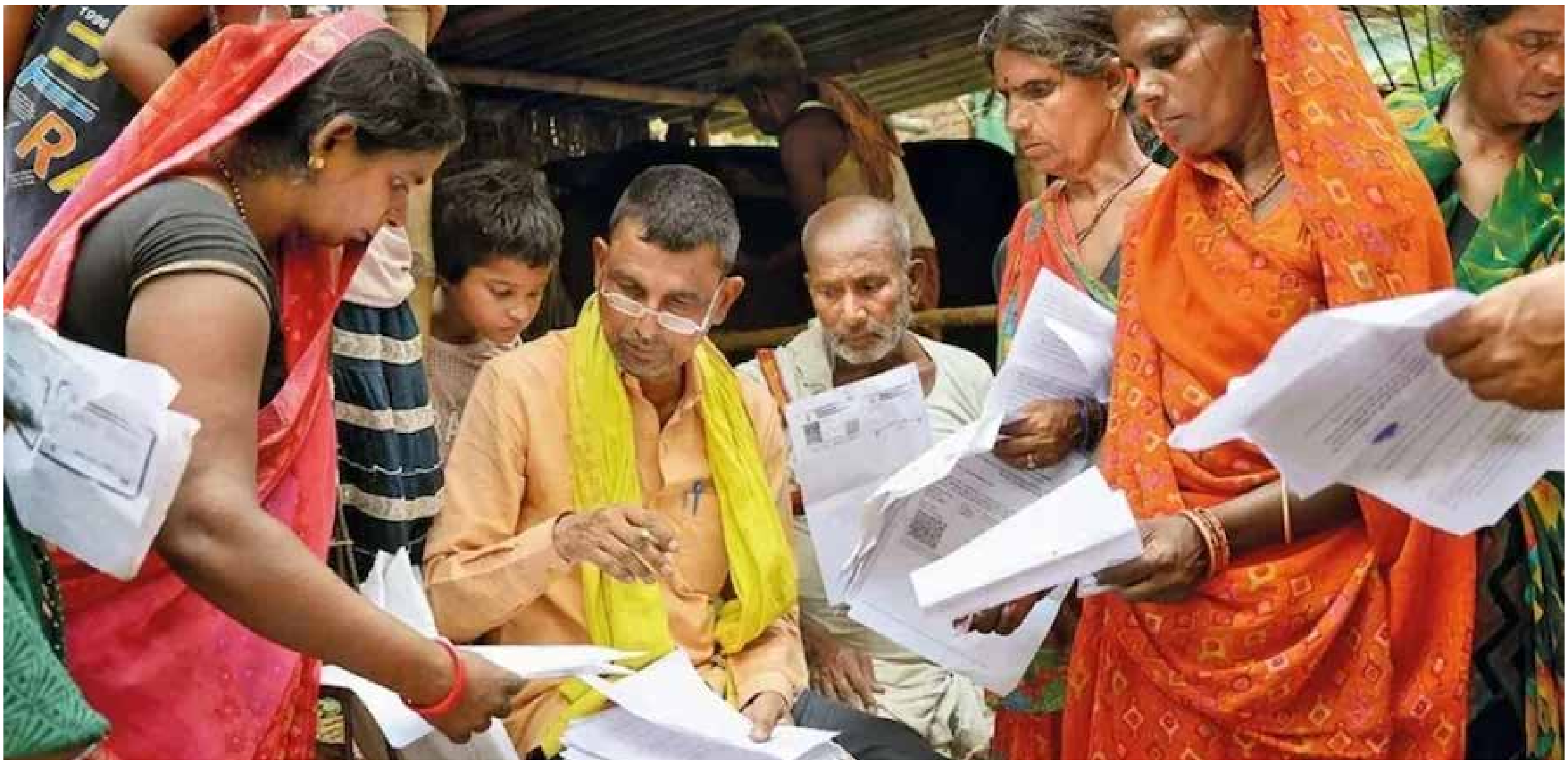

'विपक्ष की बोलती बंद' SIR वाले फैसले पर RJD ने कहा- 'हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी'

SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेडीयू विपक्ष पर हमलावर है. जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर ऐतिहासिक फैसला दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एसआईआर का उद्देश्य लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना नहीं है. जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सही माना है. कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष को एसआईआर पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए. इन दो वजहों जनसंख्या में वृद्धि और पलायन से एसआईआर बेहद महत्वपूर्ण है. एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सही दिशा में है और आगे भी जारी रहेगा. मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद विपक्ष की बोलती बंद होनी चाहिए. इसी के साथ एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने से खुद को चुप रखना चाहिए. बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से चलता है. चुनाव आयोग के सारे अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं. लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को संविधान से ज्यादा मानते हैं. ऐसे लोग एसआईआर के खिलाफ थे, जैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलाश यादव. ये लोग अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं. समस्या यह नहीं कि विरोध करना है, बल्कि समस्या यह है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करना है. पिछले दिनों चुनाव आयोग को गालियां दी गई कि

नागरिकों के नाम काट रहे हैं. क्या आप घुसपैठियों को नागरिक बना रहे हो? इन लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है. वहीं एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी. उन्होंने कहा कि हमने किसी को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि हम इंक्लूजन की जगह एक्सक्लूजन की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे. अब देखते हैं आगे क्या करना है? आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं. महज चंद सौ लोगों के हक में इंक्लूजन हुआ. हमने चुनाव आयोग के अधिकारी को चुनौती नहीं दी थी. इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं है. दरअसल, बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर फैसला सुना दिया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में कहीं कोई खामी नहीं है. यह इलेक्शन कमीशन का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि एसआईआर पूरे देश में चलता रहेगा. अदालत ने कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी कानूनी प्रकिया का पालन किया. कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग के पास वोटर को शामिल करने से इंकार का अधिकार है.

स्कूलों में RTE बना मजाक! गुस्साए पैरेंट्स नन्हे मुन्नों बच्चों के साथ आग बरसती धूप में धरने पर

शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए सख्त कानून होने के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी के चलते बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है. आरटीई का मखौल उड़ाया जा रहा है. मंदसौर में एडमिशन के लिए पैरेंट्स ने बार-बार स्कूलों के चक्कर काटने और प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद एडमिशन नहीं मिलने पर भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया. इसके बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों की नींद खुली. आरटीई के नियम के बावजूद मंदसौर में निजी स्कूलों के संचालक बच्चों को एडमिशन देने से इनकार कर रहे हैं. नियम के मुताबिक प्रत्येक निजी स्कूल में 25 प्रतिशत सीटे आरटीई के कोटे मुताबिक रिजर्व रखी जाती हैं. इनमें सामान्य और गरीब तबके के बच्चे निजी स्कूलों में भी पढ़ाई कर सकते हैं. नियम के मुताबिक इन बच्चों की फीस शासन भरता है. लेकिन मंदसौर के कई निजी स्कूल इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. महीने भर पहले पालकों ने शासन के पोर्टल पर बच्चों के एडमिशन की ऑनलाइन फॉर्म भर दिए. जब उनका सिलेक्शन संबंधित स्कूलों में हो गया तो भी स्कूल प्रबंधन बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं.

इन हालातो में पालकों ने मामले की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन से की लेकिन स्कूल प्रबंधन की मनमानी के आगे एडमिशन नहीं मिल पाया.

इसके बाद नाराज पालक अपने-अपने बच्चों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए. दोपहर 12:00 बजे बच्चों के साथ पैरेंट्स ने धरना देना शुरु किया. घंटे भर बाद जिला शिक्षा अधिकारी टेरेसा मिंस और अनुविभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने चिलचिलाती धूप से बच्चों को उठाकर बरामदे में बुलाया. अधिकारियों ने तत्काल मामले की छानबीन शुरू कर स्कूल संचालकों को फटकार लगाई. पैरेंट्स का कहना है कि पोर्टल पर एडमिशन के लिए तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर देने के बावजूद निजी स्कूल के संचालक शासन की ऑनलाइन फीस भरने की प्रक्रिया को नहीं मान रहे हैं. वह पहले ही एडमिशन फीस भरने हेतु दबाव डाल रहे हैं. दूसरे स्कूलों में भी प्रबंधन सीटें भर जाने का बहाना बना रहे हैं. ऐसे में नियम के मुताबिक बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है.अभिभावक दीपक सिंह चौहान ने अफसरों को स्कूलों की मनमानी बताई. जिला शिक्षा अधिकारी टेरेसा मिंज ने बताया "यह मामला उनके संज्ञान में है. पोर्टल पर कई स्कूलों के नाम और बच्चों की जानकारी नहीं चढ़ने के कारण एडमिशन नहीं हो पाया था. उन्होंने अब निजी स्कूलों को लिखित आदेश जारी कर बच्चों को प्रवेश देने की हिदायत दी है."

स्कूलों में मेनस्टुएशन पैड, वाटर कूलर नहीं मिला तो घूमा दें टोल-फ्री नंबर : रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए कई ऐतिहासिक और बड़े ऐलान किए हैं. अब दिल्ली के सभी स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालयों के साथ-साथ 'मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर' और मेडिकल रूम बनाए जाएंगे, जहां सैनिटरी नैपकिन से लेकर जरूरी सामग्री मुफ्त मिलेगी. इसके अलावा, छात्र-छात्राओं और अभिभावकों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए जल्द ही एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा. 5 जून से वृक्षारोपण अभियान शुरू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कमर कस ली है. छात्रों के स्वास्थ्य, हाइजीन और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कई ऐसी बड़ी घोषणाएं की हैं, जो दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में एक नया बदलाव लेकर आएंगी. इन फैसलों में सबसे ज्यादा जोर छात्राओं के स्वास्थ्य और स्कूल की बुनियादी सुविधाओं पर दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लड़कियों के हेल्थ और हाइजिन को लेकर बड़ा फैसला किया है. उन्होंने ऐलान किया कि स्कूलों में मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर बनाया जाएगा. अब सभी स्कूलों में मेडिकल रूम के साथ यह विशेष कॉर्नर स्थापित किया जाएगा, जहां छात्राओं को इमरजेंसी में सैनिटरी नैपकिन, इनरवियर और अन्य जरूरी सामान आसानी से उपलब्ध होंगे. इसके अलावा, स्कूलों के वॉशरूम में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि मासिक धर्म को लेकर सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, बल्कि नियमित हाइजीन कार्यक्रमों के जरिए लड़कों को भी जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे.

बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार अब एचपीवी (HPV) वैक्सीनेशन का स्कूलवार डेटा एकत्र करेगी. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए कितने बच्चों का टीकाकरण हो चुका है. साथ ही, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों की हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों का मानसिक और सर्वांगीण विकास हो सके. बता दें कि एचपीवी वैक्सिनेशन महिलाओं में बच्चेदानी (सर्वाइकल) कैंसर और पुरुषों व महिलाओं में अन्य जननांगों के कैंसर व मस्सों से बचाता है. सरकारी स्कूलों में अगर कोई कमी है या बच्चों व अभिभावकों को कोई शिकायत/सुझाव दर्ज कराना है, तो अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जल्द ही एक विशेष टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा.

यह नंबर स्कूलों के मेन गेट और दीवारों पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा या अभिभावक सीधे सरकार से अपनी बात कह सके. गर्मी के मौसम को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में आरओ (RO) वाटर कूलर लगाने का फैसला किया है. पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) से लेकर अगस्त तक सभी स्कूलों में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा. इसके अलावा, स्कूलों की पुताई (सफेदी) और जर्जर हो चुकी आधारभूत सुविधाओं में सुधार के काम को भी युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा.

बेटे की दिव्यांगता देख बदला मां का मन...खोला ऐसा 'मधुर' स्कूल, जो बदल रहा 'स्पेशल बच्चों' का जीवन

मां के लिए संतान की खुशी सबसे बड़ा सुख होती है. बच्चे की पीड़ा उसे झकझोर देती है. कुछ ऐसा ही हुआ चूरू की अंजू नेहरा के साथ. अपने दिव्यांग बेटे की स्थिति से उबरते हुए सैकड़ों परिवारों की उम्मीद बन गई. ये ऐसे परिवार हैं, जिनमें विशेष बच्चे हैं. अंजू एक दशक से मधुर स्पेशल शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान चला रही हैं, जहां 80 से अधिक दिव्यांग बच्चों को निशुल्क शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनने की सीख दी जा रही है. अंजू नेहरा ने बताया कि बेटे मधुर के जन्म के कुछ समय बाद दिव्यांग होने का पता चला. इससे परिवार एक बार सदमे में आ गया. बेटे को विशेष स्कूल में दाखिला दिलाया तो वहां अन्य बच्चों की स्थिति देखकर पीड़ा बढ़ गई. दिव्यांग बेटे का मुंबई में इलाज न हो पाने की हताशा ने अंजू के जीवन का लक्ष्य ही बदल दिया. अंजू ने खुद को संभाला एवं दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया. स्पेशल बच्चों के लिए मधुर स्पेशल शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान खोला. जहां 13 साल से निशुल्क तालीम दे रही हैं. अंजू आज 80 स्पेशल बच्चों की अभिभावक बन इनका भविष्य संवार रही है.स्कूल खोलने के लिए अंजू ने मुंबई जाकर स्पेशल डीएड कोर्स किया. लौटकर चूरू में निशुल्क स्कूल शुरू कर दिया. शुरुआत आसान नहीं थी. लोगों में जागरूकता की कमी थी. कई परिवारों ने अपने बच्चों को मधुर स्कूल भेजने में हिचकिचाहट दिखाई. अंजू खुद घर-घर जाकर लोगों को समझाती थी कि विशेष बच्चों को भी शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरत होती है. धीरे-धीरे बच्चों में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे तो अभिभावकों का भरोसा बढ़ा. आज यह संस्थान जिले में विशेष बच्चों की उम्मीद का बड़ा केंद्र बन चुका है. वर्ष 2013 में केवल दो बच्चों से इस स्कूल की शुरुआत हुई थी.

मधुर संस्थान में मानसिक विमंदित, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी और मूकबधिर सहित हर तरह के दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं. संस्थान में स्पेशल एजुकेटर बच्चों को फ्लैश कार्ड और विशेष पद्धतियों से पढ़ाते हैं. संस्थान की शिक्षिका सुदेश और सुमन कंवर ने बताया कि बच्चों को सबसे पहले दैनिक जीवन की जरूरी आदतें सिखाते हैं. जैसे उठना-बैठना, खाना खाना, कपड़े पहनना, बाथरूम का उपयोग और खुद की देखभाल. इसके बाद सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं. बच्चों को फूलों की माला, पेपर प्लेट बनाना, योग, व्यायाम, खेलकूद, डांस, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी जैसी गतिविधियों से जोड़ते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें. अंजू ने बताया कि कई बच्चे ऐसे भी आए, जिन्हें परिजन संभाल नहीं पाते थे. कुछ बच्चों को घरों में बांधकर रखा जाता था. उन्हें शौचालय तक की समझ नहीं थी, लेकिन नियमित प्रशिक्षण और देखभाल के बाद उनमें बड़ा बदलाव आया. कई बच्चे, जो कभी बंधनों में रहते थे, आज सामान्य जीवन जी रहे हैं. संस्थान की मदद से कई परिवारों की परेशानियां कम हुई. अंजू ने बताया कि इस सेवा कार्य में नौसेना से रिटायर्ड पति का बड़ा सहयोग रहा. पति की पेंशन का बड़ा हिस्सा स्कूल संचालन में जाता है.

RAFTAAR MEDIA
सच के साथ
Satellite News Channel
24X7
Also Available on All Leading MSO & OTT Platform
dailyhunt
DPTV LIVE
24/7
DISPLAY TV
Prime max TV
Joytv
airtel 658
Jio TV 276
TATA sky coming soon
Also Available on cable network
netvision 271
MCN 231
NXT DIGITAL 132
ALISHA DIGITAL 295
DEN 894
GTPL 280
RANCHI DIGITAL TV 28
ABPL 324
ADN 15
Jio Fiber
JioNews
airtel xstream
PLAYBOXTV One Stop Entertainment
GET IT ON Google Play
Download on the App Store coming soon
@raftaarmedia @raftaarmedia @raftaarmedia @raftaarmedia47
www.raftaarmedia.com

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का धारचूला दौरा भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर का लिया जायजा

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सीमांत पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर रहे. जहां उन्होंने धारचूला में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं सीमा प्रबंधन का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति हैं, उनका समर्पण पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के धारचूला हैलीपेड पहुंचने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया. इस अवसर पर आईजी अमित कुमार, उप महानिरीक्षक सुधांशु नौटियाल, पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ अक्षय कोंडे, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे. उनके साथ आईटीबीपी के आईजी मनु महाराज भी शामिल रहे.

भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मौजूद झूला पुल का किया निरीक्षण: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने काली नदी पर स्थित इंडो-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के धारचूला झूला पुल का निरीक्षण किया. इस अवसर पर 11 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, डीडीहाट के कमांडेंट डॉ. अतुल कुमार राय, उपजिलाधिकारी धारचूला आशीष जोशी और सहायक कमांडेंट दीपक सापकले ने उनका स्वागत किया. निरीक्षण के दौरान कमांडेंट ने क्षेत्राधिकार (AOR) और सशस्त्र सीमा बल की बॉर्डर इंटरेक्शन टीम (BIT) की कार्यप्रणाली एवं सीमा क्षेत्र में किए जा रहे सुरक्षा प्रबंधन संबंधी कार्यों की विस्तृत ऑपरेशनल ब्रीफिंग की. वहीं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीओपी धारचूला का दौरा कर सीमा पर तैनात जवानों से संवाद किया. उन्होंने जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, समर्पण एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनके योगदान की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया. अपने दौरे की स्मृति में गृह राज्य मंत्री ने बीओपी धारचूला परिसर में चंदन (सैंडलवुड) का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया. उनका यह दौरा सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा एवं जवानों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

निरीक्षण के दौरान कमांडेंट ने क्षेत्राधिकार (AOR) और सशस्त्र सीमा बल की बॉर्डर इंटरेक्शन टीम (BIT) की कार्यप्रणाली एवं सीमा क्षेत्र में किए जा रहे सुरक्षा प्रबंधन संबंधी कार्यों की विस्तृत ऑपरेशनल ब्रीफिंग की. वहीं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीओपी धारचूला का दौरा कर सीमा पर तैनात जवानों से संवाद किया. उन्होंने जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, समर्पण एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनके योगदान की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया.

चमोली में जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची, सड़क किनारे खड़ी कार जली

उत्तराखंड के चमोली जिले में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. अब जंगलों की आग जिला मुख्यालय गोपेश्वर के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है. ताजा मामला गोपेश्वर स्थित नर्सिंग कॉलेज के पास का है, जहां जंगल में लगी आग अचानक सड़क किनारे तक पहुंच गई. तेज धूप और तेज हवाओं के चलते आग भयानक तरीके से फैल गई. आग की लपटें सड़क किनारे खड़े वाहनों तक पहुंच गईं, जिससे एक वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया. घटना के दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग भयभीत हो उठे. घटना की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई. दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक एक वाहन पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था. हालांकि. बाद में आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. चमोली जिला मुख्यालय से लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक वनाग्नि से नुकसान हो रहा है. वन विभाग और प्रशासन के सामने आग पर नियंत्रण बड़ी चुनौती बना हुआ है. गौर हो कि बीते दिनों गैरसैंण विकासखंड के आदिबदरी तहसील के बूंगा गांव की

सुरेशी देवी (उम्र 51 वर्ष) जंगल की आग की चपेट से बुरी तरह से झुलस गई. जिसके बाद उसने दर्द और जलन से कहराते-कहराते दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि बीती 26 मई यानी मंगलवार देर शाम करीब 7 बजे के आसपास बूंगा गांव की सुरेशी देवी अपनी गौशाला जा रही थी. तभी जंगल में लगी आग उनकी गौशाला तक पहुंच गई. जिसके चपेट में आने से सुरेशी देवी गंभीर रूप से झुलस गई. जिससे उनकी मौत हो गई. बारिश से धीरे-धीरे शांत होने लगी जंगलों धधक रही आग: इधर, शाम होते-होते मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. बारिश होने से जंगलों में धधक रही आग धीरे-धीरे शांत होने लगी है. साथ ही भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं.

मेरठ में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट 23 दिन बाद लोगों को मिला खेत में दबा शव

जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के गांव महमूदपुर सिखेड़ा में पिछले करीब 23 दिनों से लापता एक युवक की उसके ही सगे बड़े भाई ने बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को एक खेत में छिपा दिया था. इस खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. महमूदपुर सिखेड़ा निवासी 32 वर्षीय अंकुर पुत्र बाबूराम बीते 5 मई 2026 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था. परिजनों और रिश्तेदारों द्वारा उसकी काफी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था. अंकुर की मौसी जयवीरी (पत्नी खिताब) ने इस मामले में थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हो सका. अंकुर की मौसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अंकुर के बड़े भाई कपिल को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की. कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी कपिल टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. कपिल ने बताया कि उसने जमीनी विवाद के चलते 5 मई को ही अपने छोटे भाई अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को खेत में ही

दबा दिया था. मृतक अंकुर तीन भाइयों में सबसे छोटा था. ग्रामीणों के मुताबिक, करीब चार साल पहले अंकुर की पत्नी की भी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वह अकेले ही रह रहा था. इस दुखद घटना के बाद अंकुर की दो मासूम बेटियां पूरी तरह से अनाथ हो गई हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे. सीओ मवाना पंकज लमानी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही सभी कानूनी पहलुओं को पूरा कर लिया जाएगा. SP देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि थाना बहसूमा में महमूदपुर सिखेड़ा गांव की रहने वाली एक महिला जयवीरी ने आकर सूचना दी कि उनका 30 वर्षीय भांजा अंकुर बीती

सख्ती से की गई पूछताछ में कपिल ने स्वीकार किया कि उसने जमीनी विवाद के चलते 5 मई को अपने छोटे भाई अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और शव को खेत में रख (दबा) दिया था. मौके पर बहसूमा पुलिस और FSL (फॉरेंसिक) की टीम मौजूद है. पुलिस ने शव को क जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी भाई के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

5 मई से गांव से गायब है। उन्होंने अपने बड़े भांजे कपिल पर अंकुर की हत्या करने का शक जताया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कपिल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया.

रायपुर में नेशनल मैंगो फेस्टिवल, राज्यपाल रमेन डेका करेंगे शुभांरभ, आम प्रेमियों के लिए अच्छा मौका

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार से अगले तीन दिनों तक आम की कई किस्मों का प्रदर्शन होगा. यह आयोजन 29 मई से 31 मई तक चलेगा. इसका आयोजन संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ सरकार और प्रकृति की ओर सोसायटी की तरफ से किया गया है. राष्ट्रीय आम महोत्सव 2026 का शुभांरभ राज्यपाल रमेन डेका शुक्रवार की शाम 4 बजे करेंगे. उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे. कृषि मंत्री रामविचार नेताम, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चन्द्रहास चन्द्राकर , छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे.

राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जायेगा. यहां आम की उन्नत किस्मों के पौधे और फल भी बेचे जाएंगे. राष्ट्रीय आम महोत्सव में विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित आम की व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत दशहरी, लंगड़ा, बाम्बे ग्रीन, चौसा, मालदा, हिमसागर और सुन्दरजा आम को प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा. इसके अलावा केसर, अलफान्सो, तोतापरी, नीलम, बैगनफल्ली, पैरी, सिन्दूरी, फ़ज़ली आदि किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी.

संकर किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत मल्लिका, आम्रपाली, पूसा अरुणिमा, अम्बिका, रत्ना, सिंधु, अर्का पुनीत किस्मों को शामिल किया गया है. विशिष्ट किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत हाथीझुल, नूरजहां, लड्डू, गुलाब खास किस्मों के उत्पादक भाग ले सकते हैं. एक्जोटिक (आयातित किस्म) की प्रतियोगिता में मियाजाकी, टॉमी एटकिन्स एवं गोल्डन नगेट्स किस्मों को शमिल किया गया है. आम महोत्सव में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है. जिसमें छत्तीसगढ़ एवं देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे. यहां छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए आम उत्पादक किसान उनके द्वारा उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन करेंगे.

आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी. आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय आम महोत्सव में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं. आम महोत्सव के दौरान आम पर केंद्रित मैंगो क्विज़ मैंगो, फैंसी ड्रेस आदि प्रतियोगिताएं भी अयोजित की जाएगी. इसके अलावा प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा.

कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल, वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस, 3 युवकों को पकड़ा

शहर के सीतामणी चौक में बीच सड़क युवक को अधमरा होने तक बेरहमी से पीटने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. घटना के आंठवे दिन बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है. 20 मई की रात करीब 10:45 बजे इस वारदात को दर्जन भर से अधिक युवकों ने अंजाम दिया था. घटना की सूचना पुलिस को उसी रात मिल गई थी लेकिन तब एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी. मारपीट में घायल युवक की हालत गंभीर हो गई. 26 मई को इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. तब जाकर पुलिस हरकत में आई और अब 28 मई को तीन युवकों को गिरफ्तार कर उनके जुलूस निकाला गया है. पुलिस ने करीब 8 दिन बाद यह कार्रवाई की है.

कोतवाली थाना अंतर्गत रमेश गली सीतामणी निवासी रोशन शर्मा 20 मई को रात करीब 10:45 बजे सीतामणी चौक से कुछ सामान लेने गया था. सीतामणी चौक में डिक्सेना दुकान से सामान लेकर वह निकला ही था कि उसी समय सीतामणी के नागेश मद्रासी, रिंकू यादव, आलोक यादव और अन्य लोग आए. उसके बाद उन लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर रोशन शर्मा से गाली गलौच करना शुरू कर दिया. जान से मारने की धमकी देते हुए इन लोगों ने हाथ-मुक्का, ईटा एवं पंचिंग से मारपीट किये. मारपीट से रोशन शर्मा के सिर, चेहरा, सीने और पूरे बदन में चोट आयी, घटना के बाद रोशन शर्मा को थाना कोतवाली से जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया. रोशन को 14 टांके लगे है. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में इलाज के लिए उसे रायपुर रेफर किया गया. वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित के भाई रजनीश शर्मा की रिपोर्ट पर नागेश मद्रासी, रिंकू यादव, आलोक यादव एवं अन्य लोग के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया. सभी के खिलाफ धारा 115(2)-, 296, 3(5)-, 351(3)-BNS के तहत जुर्म दर्ज किया गया था. जिन्हें 28 मई को गिरफ्तार किया गया घटना के संज्ञान में आने उपरांत जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के सख्त मार्गदर्शन में 26 मई को अपराध दर्ज किया गया. आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में जुर्म दर्ज किया गया. इसके पश्चात 28 मई को तीन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की इलाके में व्याप्त दहशत को कमजोर करने के लिए पुलिस ने इन तीनों अपराधियों का घटना स्थल से लेकर कोतवाली तक जुलूस निकाला गया.

स्थानीय युवक आजाद बख्श और मोहल्लेवासियों ने कोतवाली पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है. जिसमें अपराध के प्रभावी नियंत्रण की मांग की गई है. आजाद ने बताया कि घटना 20 मई की है. जब सीतामणी चौक में एक बच्चे को 20 से अधिक लोगों ने बेरहमी से मारा, उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए. आजाद बख्श ने आगे कहा कि यह वीडियो जब वायरल हुआ तब सीएसपी साहब ने कहा कि वीडियो वायरल होने की वजह से अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है.

कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई

चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपना एक्स अकाउंट ब्लॉक करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच इसपर सुनवाई करेगी. अभिजीत दीपके ने वकील नकुल गांधी के जरिये हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के आधार पर ब्लॉक किया गया था. इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से एक्स अकाउंट ब्लॉक करने की सिफारिश की थी. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक्स को कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था.

बता दें कि, कॉकरोच जनता पार्टी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन के रूप में उभरा. दरअसल, 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था ऐसे कई बेरोजगार युवा जिन्हें न तो रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई ठिकाना तो वे आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट या अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और पूरे सिस्टम पर हमला करने लग जाते हैं. कोर्ट ने कहा था कि कुछ वकीलों खासकर दिल्ली में लॉ डिग्रियों की प्रामाणिकता की सीबीआई जांच की जरूरत है. बाद में चीफ जस्टिस ने इस मामले पर सफाई भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को किस तरह गलत तरीके से पेश किया है. मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी, जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की मदद से वकालत जैसे व्यवसायों में प्रवेश किया है.

दिल्ली के खजूरी खास में 'गैंगवार'! अक्की डॉन की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या

राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब अज्ञात बदमाशों ने 'राजा उर्फ अक्की डॉन उर्फ आकिल' नाम के शख्स की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है. यह सनसनीखेज वारदात खजूरी खास के एफ ब्लॉक (F-Block) क्षेत्र में हुई. बताया जा रहा है कि घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने अक्की को देखते ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने अक्की पर बैक-टू-बैक कई राउंड फायर किए, जिसमें से करीब तीन गोलियां उसे सीधे लगीं. फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा खून से लथपथ अक्की को तुरंत गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया.

अक्की डॉन का था आपराधिक रिकॉर्ड, गैंगवार की आशंका मारे गए शख्स यानी राजा उर्फ अक्की डॉन का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. इसी वजह से पुलिस इस पूरे मामले को आपसी रंजिश (Personal Enmity) और गैंगवार (Gang War) के एंगल से जोड़कर देख रही है. आशंका जताई जा रही है कि किसी पुरानी दुश्मनी के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है. वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी खौफ है. माहौल न बिगड़े, इसे देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन घटना स्थल और आसपास के पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है. पूरे मामले पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राहुल अलवल ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया पुलिस ने शव को अपने क जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस घटना स्थल और उसके आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है बदमाशों को दबोचने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

बदमाशों ने अक्की पर बैक-टू-बैक कई राउंड फायर किए, जिसमें से करीब तीन गोलियां उसे सीधे लगीं. फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा खून से लथपथ अक्की को तुरंत गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया.

देश की राजनीति अब हुई महिला केंद्रित

योजनाओं और दावों के जरिए महिला वोटरों को साधने की नई रणनीति

सौरभ राय/रफ्तार मीडिया
विशेष संवाददाता

रांची : देश को विकास और उन्नति की ओर ले जाने में महिलाओं की अहम भागीदारी रही है आदि काल से ही महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी और वर्तमान में भी हर छेत्र में महिलाओं की सहभागिता देखी जा रही है। इस बीच भारतीय राजनीति में भी महिलाएं केंद्र बिंदु के तौर पर उभर कर सामने आ चुकी हैं।महिलाएं अब केवल वोटर नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है जिस कारण हाल में हो रही विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की नीतियों, घोषणापत्रों और चुनावी अभियानों में महिलाओं को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भारतीय राजनीति में यह एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है आज उज्जवला योजना, मैया सम्मान योजना से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बहस साफ तौर पर उजागर कर रही हैं कि देश की राजनीति में अब महिलाएं एक सेंट्रल प्वाइंट पर आ गई है। राजनीतिक दलों को केवल वोट बैंक नहीं बल्की सामाजिक सुधार के लिए कार्य करने की आवश्यकता महिला केंद्रित राजनीति हमारे देश एवं लोकतंत्र के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। यदि यह पहल केवल चुनावी वोट बैंक तक सीमित न रहकर वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ती है, तो इसका प्रभाव समाज के हर स्तर पर दिखाई देगा।

महिलाओं के लिए चलाई जा रही है कई योजनाएं : देश की आधी आबादी को सशक्त एवं सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के योजनाएं चलाए जा रहे हैं।इनमें आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ी पहलें शामिल हैं। केंद्र सरकार की चर्चित योजनाओं में से एक उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मुहैया कराया जा रहा है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चल रही है जिसके जरिए बहन बेटियों को शिक्षा दिलाया जा रहा है। इसके साथ साथ लखपति दीदी योजना के तहत केंद्र सरकार देश की लगभग 2 करोड़ महिलाएं मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कि स्वयं सहायता समूहों के साथ कार्य करती हैं उन्हें साल में कम से कम एक लाख रुपए तक कमाने का अवसर प्रदान करती है।

मैया सम्मान योजना के जरिए झारखंड में सत्ता की वापसी : वर्ष 2024 में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम पुन: झामुमो और महागठबंधन के पक्ष में आई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना हैं कि यह केवल एक चुनावी प्रचार प्रसार के कारण नहीं हुई बल्कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की सरकार द्वारा शुरु की गई मैया सम्मान योजना के कारण हुई है। बता दे, झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2023 में मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए प्रत्येक माह भेजे जा रहे थे जिसके बाद युक्त योजना की राशि बढ़ाकर 2500 भेजना प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार का दावा है कि इस योजना के जरिए झारखंड की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं एवं कई छात्राओं की पढ़ाई में भी यह राशि उपयोगी साबित हो रही है।

राजनीति में बढ़ती भागीदारी एवं बढ़ता प्रभाव

भारत में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर देश की आधी आबादी की जनसंख्या को लेकर चर्चा की जाए तो वर्तमान वर्ष 2011 में हुए जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या लगभग 586.47 मिलियन थी। कई राज्यों में तो महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी अधिक दर्ज किया गया है। इस बदलाव के कारण राजनीतिक दल भली भांति समझ गए हैं कि अगर सत्ता में रहना है तो को महिला वोटरों का समर्थन हासिल करना अनिवार्य होगा।

योजनाओं के जरिए महिलाओं का विश्वास जीतने की रणनीति

इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना है, लेकिन इसके साथ ही यह राजनीतिक समर्थन जुटाने का एक प्रभावी माध्यम भी बन चुका है। झारखंड की पड़ोसी राज्य बिहार में भी महिलाओं को प्रदान की जा रही राशि बढ़ाकर 10,000 कर दी गई जिसका लाभ विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। यह कहना कदापि गलत नहीं होगा कि अब देश की महिलाएं "लाभार्थी वर्ग" के रूप में उभर रही हैं। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने से उनमें सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से महिलाओं के विश्वास को जीतने के लिए योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं।

चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं की प्राथमिकता

अब लगभग हर पार्टी अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए विशेष वादे करती है चाहे वह मुफ्त बस यात्रा हो, मासिक भत्ता, या रोजगार के अवसर। पश्चिम बंगाल, असम , तामील नाडू और पुदुच्चेरी जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे है इन चुनावों में तमाम राजनेता महिलाओं के उन्नति के लिए योजनाएं लाने का दावा कर रहे हैं तो वहीं जो राज्य सरकार मौजूद है वह महिलाओं के लिए किए गए कार्यों को गिना रही हैं। झारखंड का पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल टीएमसी और भाजपा के बीच जमकर ज़ुबानी जंग तेज हुई जहां एक ओर टीएमसी अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही लखी भंडार योजना के तहत प्रत्येक महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं इसका प्रचार कर रही है तो वहीं भाजपा महिला वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए दावा कर रही है कि अगर वह सरकार में आई तो मातृ शक्ति वंदन योजना के तहत 3000 रुपए प्रत्येक माह महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे। ऐसे दावे और योजनाएं से हम कह सकते हैं कि अब "महिला सम्मान राशि" जैसी योजनाएं देश में एक ट्रेंड बन चुकी हैं।

चुनौतियां अब भी कायम

देश की राजनीति में महिलाओं के बढ़ती प्रभाव सकारात्मक संदेश जरूर देता है है, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं क्या योजनाएं वास्तव में सशक्तिकरण कर रही हैं या केवल वोट बैंक की राजनीति है? क्या महिलाओं को दी जा रही सुविधाएं स्थायी विकास की ओर ले जा रही हैं? क्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है? क्या महिलाओं के दुष्कर्म जैसी जघन्य अपराध में काबू पाया गया है? क्या अब भी छात्राएं बेखौफ होकर स्कूल और कॉलेज जा पाती है? क्या अब भी कॉरपोरेट कार्यालयों में महिला कर्मचारी खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है?

सामाजिक बदलाव की झलक

राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका केवल वोट तक सीमित नहीं है। पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इससे नीतियों में भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अधिक जगह मिल रही है। इस बीच पिछले 17 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाई गई थी जिसके द्वारा कहा जा रहा था कि अब लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के विरोध के कारण यह अधिनियम संसद में पारित नहीं हो पाई।

झारखंड की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बना चर्चा का विषय

अगर झारखंड की राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा की तो राज्य में निश्चित तौर पर महिलाओं की सहभागिता पूर्व की तुलना में बढ़ी है। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 10 महिला विधायक थी अब 2024 के विधानसभा चुनाव में 13 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुई। वर्तमान में झारखंड सरकार में दो महिला मंत्री हैं जिनमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पाण्डे सिंह और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल है। वहीं, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन की राजनीति में आना झारखंड की महिलाओं को प्रेरित किया। राजधानी रांची में भी महिला प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है पहले दो बार डॉक्टर आशा लकड़ा ने महापौर के तौर पर रांची का प्रतिनिधित्व किया वर्तमान में वह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य है। वहीं तीन वर्षों के बाद नगर निकाय के चुनाव हुए जिसमें रांची से रौशनी खलखो ने जीत हासिल कर पार्षद से महापौर बनने का सफर तय कर लिया।

मुख्यमंत्री राहत कोष का हिसाब मांग रहा CMO, पांच साल पहले हुए खर्च को लेकर विभागों को लिखा लेटर

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र लिखकर 5 साल पहले हुए खर्चों का हिसाब मांगा जा रहा है. साथ ही विभागों को हिसाब के बारे में याद भी दिलाया जा रहा है. हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बार-बार कहे जाने के बाद भी आवंटित बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा जा रहा है. जिसके कारण मुख्यमंत्री राहत कोष के हिसाब को तैयार करने में भी दिक्कतें आ रही हैं. मामला मुख्यमंत्री राहत कोष से जुड़ा है. मामला कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न विभागों को जारी किए गए बजट और उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी (Utilization Certificate) से संबंधित है. करीब पांच साल बीत जाने के बाद भी कई विभाग खर्च किए गए करोड़ों रुपये का पूरा हिसाब शासन को नहीं दे पाए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार विभागों को पत्र भेजकर याद दिला रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई विभाग इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहे. कोविड के दौरान वित्तीय खर्च की फाइल: कोविड संक्रमण अब लोगों की यादों से लगभग धुंधला पड़ चुका है, लेकिन शासन के भीतर उस दौर से जुड़ी फाइलें अब भी अधूरी हैं. महामारी के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री राहत कोष से अलग-अलग विभागों को करोड़ों रुपए जारी किए गए थे. इन पैसों का इस्तेमाल यात्रियों को उनके घर पहुंचाने, वैक्सीनेशन अभियान चलाने, अस्थायी चिकित्सालय स्थापित करने और जरूरतमंद वर्गों की सहायता जैसे कार्यों में किया गया. लेकिन इन खर्चों का अंतिम लेखा-जोखा अब तक शासन के रिकॉर्ड में पूरा नहीं हो पाया है.

दरअसल, किसी भी विभाग को जारी किए गए बजट के बाद संबंधित विभाग को यह बताना होता है कि पैसा किस काम में और किस प्रकार खर्च किया गया. इसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. यह प्रमाण पत्र वित्तीय अनुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी धन का इस्तेमाल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही हुआ है. वित्त विभाग और शासन इसी आधार पर खर्चों का अंतिम मिलान करते हैं. लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी बजट के मामले में कई विभाग वर्षों बाद भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं. यही कारण है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को बार-बार विभागों को पत्र लिखने पड़ रहे हैं. इन पत्रों में पुराने निर्देशों का हवाला देते हुए विभागों को याद दिलाया जा रहा है कि अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे गए हैं. सबसे बड़ा मामला परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है. कोविड-19 संक्रमण के दौरान लॉकडाउन और आपात स्थिति में अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में फंसे पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से लगभग 24 करोड़ रुपए जारी किए गए थे. इस धनराशि का उपयोग परिवहन व्यवस्था में किया गया, लेकिन पांच साल बीतने के बाद भी विभाग द्वारा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया. कई बार पत्राचार के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इससे यह प्रतीत होता है कि विभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा. सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इतने लंबे समय तक यूसी लंबित रहने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई. इसी तरह स्वास्थ्य विभाग को भी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र भेजा गया है. कोविड काल में 18 से 44 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए निशुल्क वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था. इसके अलावा अस्थायी कोविड चिकित्सालय भी स्थापित किए गए थे. इन कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से लगभग 130 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी. बताया गया है कि इसमें से करीब 70 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए और 10 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को सौंप दिया गया. लेकिन इसके बावजूद लगभग 50 करोड़ रुपए के खर्च का पूरा हिसाब आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है.

पांच साल तक उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने पर अब तक क्या कार्रवाई की गई

सवाल ये उठता है कि आखिर पांच साल तक उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने पर अब तक क्या कार्रवाई की गई. मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्रों में केवल यूसी उपलब्ध कराने की बात कही गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि लगातार अनदेखी करने वाले अधिकारियों या विभागों के खिलाफ कोई जवाबदेही तय हुई या नहीं. यह पूरा मामला केवल वित्तीय दस्तावेजों की देरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन की कार्यशैली और प्रशासनिक अनुशासन की वास्तविक तस्वीर भी सामने लाता है.

जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर बनी समिति कानून की आवश्यकता के संबंध में कर सकती है विचार: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले "कृत्रिम" जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस बात का भी आकलन करेगी कि इस मुद्दे से निपटने के लिए किसी कानून की आवश्यकता है या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर अवैध प्रवासी अपनी मर्जी से चले जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार उनके खिलाफ कानूनी मामले दर्ज करने से परहेज करेगी और उनके जाने में सुविधा प्रदान करेगी. शाह ने 340 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीडीसी) के गठन के संबंध में कहा गया है कि अवैध प्रवासन के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से "व्यापक चुनौतियां" उत्पन्न हुई हैं. शाह ने कहा, "उच्च स्तरीय समिति देश भर में हुए कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों के कारणों की जांच करेगी. यह आवश्यक सुधारात्मक उपायों पर विचार-विमर्श करेगी और यदि किसी विशिष्ट कानून को लागू करना आवश्यक हुआ, तो उस आवश्यकता को भी संबोधित करेगी."

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश से हर घुसपैठिए की पहचान करके उसे बाहर निकालने के लिए दृढ़ता से कटिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी उद्देश्य से जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर समिति का गठन करने का निर्णय लिया. शाह ने बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल की पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और दावा किया कि राज्य में विधानसभा चुनावों (जिसमें भाजपा सत्ता में आई) के बाद स्थिति बदल गई है. उन्होंने कहा, "अब भारतीय जनता पार्टी देश के 80 प्रतिशत भूभाग पर शासन करती है, और हाल में बंगाल में संपन्न हुए चुनावों में दीदी (ममता बनर्जी) को करारी हार का सामना करना पड़ा." शाह ने कहा कि उत्तराखंड से लेकर गंगासागर तक, गंगा के पूरे प्रवाह क्षेत्र में भाजपा "भगवा झंडा फहराने" में सफल रही. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले, भाजपा ने सत्ता में आने के कुछ ही दिन के भीतर बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू करने का वादा किया था. शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सत्ता में आने के सात दिन के भीतर ही सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को बाड़ लगाने के काम के लिए 600 हेक्टेयर भूमि सौंप दी गई. उन्होंने कहा, "इसके अतिरिक्त, चिकन नेक कॉरिडोर में 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार के हवाले कर दी गई है."

'चिकन नेक', जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला एक संकरा भूभाग है. मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए शाह ने कहा कि घुसपैठिए खुद ही बांग्लादेश लौटने लगे हैं. उन्होंने दावा किया, "जबकि ममता बनर्जी के शासनकाल में रोज घुसपैठ होती थी." केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिरासत केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि अवैध प्रवासी स्वेच्छा से अपने मूल स्थानों पर लौट जाएं. शाह ने कहा, "अगर वे अपनी मर्जी से चले जाते हैं, तो बंगाल सरकार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, साथ ही उनके जाने में सहायता भी प्रदान करेगी."

अमित शाह ने 340 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

अवैध प्रवासी अपनी मर्जी से चले जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार उनके खिलाफ कानूनी मामले दर्ज करने से परहेज करेगी और उनके जाने में सुविधा प्रदान करेगी. शाह ने 340 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

सहकार से समृद्धि
आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि
NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इफको नैनो यूरिया प्लस और
इफको नैनो डी.ए.पी.
का वादा
लागत कम और लाभ ज्यादा
FCO अधिसूचित दुनिया का पहला नैनो उर्वरक
500 मिली बोतल मात्र ₹225/- में
500 मिली बोतल मात्र ₹600/-में
इफको नैनो यूरिया प्लस (तरल)
इफको नैनो डी.ए.पी. (तरल)
IFFCO
NANO UREA PLUS
IFFCO
NANO DAP
LIQUID (8:16:0)
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, राँची (झारखण्ड)
राज्य विपणन कार्यालय: एम1 (डी/एस) हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची-834002
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 1800 103 1967; वेबसाईट : www.nanourea.in / www.nanodap.in

'देवभूमि में सड़कों पर नहीं होने देंगे नमाज, कानून व्यवस्था से समझौता बर्दाश्त नहीं', बोले उत्तराखंड सीएम

उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कहा कि 'देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे. किसी भी धार्मिक गतिविधि के नाम पर आम लोगों की आवाजाही बाधित नहीं होने दी जाएगी. प्रदेश में कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति या समूह नियमों से ऊपर नहीं हो सकता.' दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में सिंचाई विभाग एवं कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने यह बात कही. उन्होंने एक कांग्रेस नेता के बयान का जिक्र किया. सीएम धामी ने कहा कि 'कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि 'सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए. जिस पर हमने कहा कि नमाज जिस स्थान पर पढ़ी जाती है, वहीं पर नमाज होनी चाहिए. यह व्यवस्था है, इसे बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है.'

सीएम धामी ने आगे कहा कि 'इस समय चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता राज्य में शांति, सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना है.' उन्होंने कहा कि 'सड़कें आम जनता के उपयोग के लिए हैं, इसलिए उन्हें धार्मिक आयोजन या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाया जा सकता.' सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि 'नमाज मस्जिदों, ईदगाहों और प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए. सार्वजनिक स्थलों पर रास्ता रोककर लोगों को असुविधा पहुंचाना किसी भी हाल में उचित नहीं है.' उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 'कुछ राजनीतिक दल तुष्टिकरण की राजनीति के तहत सड़क पर नमाज को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट नीति पर काम कर रही है.'

सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं देंगे. आवागमन और कानून व्यवस्था में अवरोध पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की धरा है देवभूमि उत्तराखंड, यहां किसी को भी माहौल खराब करने का अधिकार नहीं है. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और सड़कों को बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि 'उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक सौहार्द से खिलवाड़ किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.' गौर हो कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर सड़क पर नमाज को लेकर तल्ख बयान देते आए हैं. वे कह चुके हैं कि 'सड़कें चलने के लिए होती है, तमाशे के लिए नहीं'. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इसी तरह के बयान दे चुके हैं.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी थी. जिसमें उन्होंने साफतौर पर कहा था सड़कें चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं. इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा था कि 'जुम्मे (शुक्रवार) के दिन कभी-कभी कतार सड़क तक पहुंच जाती है. यह कोई आम चलन नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में नमाज पढ़ना लोगों का अधिकार है, हम उनका यह अधिकार छीन नहीं सकते.'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में सिंचाई विभाग एवं कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने यह बात कही. उन्होंने एक कांग्रेस नेता के बयान का जिक्र किया. सीएम धामी ने कहा कि 'कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि 'सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए. सीएम धामी ने आगे कहा कि 'इस समय चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता राज्य में शांति, सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना है.' उन्होंने कहा कि 'सड़कें आम जनता के उपयोग के लिए हैं, इसलिए उन्हें धार्मिक आयोजन या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाया जा सकता.'

समस्या जो दिखती नहीं, पर हर खेत में मौजूद है

जहां कचरा ही बन रहा है उर्वरक और नियंत्रण ही बन रहा है ताकत नई भूमिगत कृषि प्रणाली का दावा - कचरे, ऑक्सीजन और जड़ के बीच टूटे प्रवाह को जोड़कर खेती को अधिक स्थिर और लागत-कुशल बनाया जा सकता है।

खेत के नीचे चल रही है नई खेती

रफ्तार मीडिया || संवाददाता

मुरबाड और इसी तरह की लाल मिट्टी वाली पट्टियों में खेती की असली समस्या वह नहीं है, जो अक्सर सरकारी रिपोर्टों में बताई जाती है। यह योजनाओं की कमी नहीं है, जागरूकता की कमी नहीं है और न ही इनपुट की। किसानों के पास पानी है, गोबर है, फसल का अवशेष है और वे ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी कर रहे हैं। इसके बावजूद नतीजे असंगत हैं—एक सीजन उम्मीद देता है, अगला टूट जाता है। जमीन पर जाकर जब किसानों से बात होती है, तो एक बात साफ सामने आती है: सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जड़ के स्तर पर कुछ भी नियंत्रित नहीं है।

असली विफलता: जड़ तक पहुंचने से पहले ही टूट जाता है सिस्टम

यहीं खेती की असली कमजोरी है। उर्वरक सतह पर डाला जाता है, खाद खेत के एक कोने में तैयार होती है, सिंचाई पाइप से होती है और जरूरत पड़ने पर माइक्रोबियल उत्पाद मिलाए जाते हैं। लेकिन पौधे की जड़ - जो पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है - इन सभी इनपुट्स को अनियमित तरीके से प्राप्त करती है। भारी बारिश में पोषक तत्व बह जाते हैं, सूखे में नमी अचानक गिरती है, जैविक पदार्थ धीरे-धीरे और अधूरा टूटता है, समस्या प्रयास की कमी नहीं, बल्कि "कचरे से जड़ तक" के प्रवाह के टूटने की है।

फिल्ट्रेशन: जहां अधिकांश सिस्टम विफल होते हैं

अधिकांश खेतों में घोल बनने के बाद उसे सीधे उपयोग कर लिया जाता है या फेंक दिया जाता है - और यहीं सिस्टम टूट जाता है। इस मॉडल में तरल को बजरी, रेत और बायोचार की मल्टी-लेयर निस्पंदन इकाई से गुजारा जाता है। यह विकल्प नहीं, बल्कि सिस्टम का स्थायी हिस्सा है। इसका उद्देश्य साफ पानी बनाना नहीं, बल्कि ऐसा तरल तैयार करना है: जो स्थिर हो, पाइपलाइन को बंद न करे, लंबे समय तक उपयोग योग्य रहे, बिना इस चरण के कोई भी भूमिगत प्रणाली टिकाऊ नहीं हो सकती।

नया दृष्टिकोण: सिस्टम को जोड़ने की कोशिश

अब जमीन पर जो विकसित हो रहा है, वह कोई नया इनपुट नहीं है - बल्कि इस टूटे हुए प्रवाह को जोड़ने का प्रयास है। इस प्रणाली में अपशिष्ट, ऑक्सीजन, निस्पंदन और जड़ को एक ही भूमिगत चक्र में जोड़ा जाता है। गोबर और फसल अवशेष अब बाहर खाद बनाकर बाद में डालने वाली चीज़ नहीं रह जाते। उन्हें सीधे एक भूमिगत संरचना में डाला जाता है, जहां अपघटन सिस्टम के अंदर ही होता है। लेकिन यह पारंपरिक खाद गड्ढा नहीं है।

नैनो बबल तकनीक: अपघटन को तेज करने की कुंजी

इस प्रणाली में नैनो बबल ऑक्सीजन को नियंत्रित तरीके से जोड़ा जाता है, जिससे माइक्रोबियल गतिविधि सामान्य खाद से अलग व्यवहार करती है। **वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि:** एंजाइम गतिविधि बढ़ती है, कठोर पदार्थ (जैसे पुआल) तेजी से टूटते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की उपलब्धता बेहतर होती है, यानी जो प्रक्रिया सामान्यतः धीमी होती है, वह तेज और अधिक प्रभावी हो जाती है।

जड़ तक सीधी आपूर्ति असली बदलाव यहीं है

फिल्ट्रेशन के बाद तरल को सतह पर नहीं लाया जाता, बल्कि उपसतही नेटवर्क के जरिए सीधे जड़ क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। यहीं से यह प्रणाली पारंपरिक खेती से अलग हो जाती है। पौधा अब सतही उर्वरक पर निर्भर नहीं नमी बेहतर बनी रहती है, पोषक तत्व कम नष्ट होते हैं, जड़ को अचानक तनाव नहीं झेलना पड़ता

ऑक्सीजन नियंत्रण बारिश पर निर्भरता कम

नैनो बबल तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि ऑक्सीजन प्राकृतिक उतार-चढ़ाव पर निर्भर न रहे। अध्ययन बताते हैं कि घुलित ऑक्सीजन बढ़ाने से: जड़ श्वसन बेहतर होता है, पोषक तत्व अवशोषण बढ़ता है माइक्रोबियल संतुलन सुधरता है, जो काम किसान बारिश पर निर्भर होकर करते थे, वह अब नियंत्रित रूप में संभव होता है।

अलग क्या है?-घटक नहीं, उनका संयोजन

इस प्रणाली में कोई एक चीज़ नई नहीं है। नैनो बबल तकनीक पहले से मौजूद खाद बनाना पहले से मौजूद, ड्रिप सिंचाई मौजूद, फिल्ट्रेशन मौजूद, लेकिन ये सब अलग-अलग उपयोग होते हैं। यहां पहली बार ये सब एक सतत चक्र में जुड़े हैं - जहां अपशिष्ट बाहर निकले बिना संसाधित, सक्रिय, फ़िल्टर और जड़ तक पहुंचता है।

मैदान पर असर: स्थिरता और लागत में बदलाव

जब पोषक तत्वों का नुकसान कम होता है और जड़ का वातावरण स्थिर होता है, तो पौधे की वृद्धि अधिक सुसंगत हो जाती है। **अध्ययन संकेत देते हैं कि ऑक्सीजन-समृद्ध प्रणालियां:** उपज बढ़ा सकती हैं, फसल की गुणवत्ता सुधार सकती हैं, लेकिन इससे भी बड़ा असर लागत पर पड़ता है - खेत का कचरा ही इनपुट बन जाता है, जोखिम भी उतने ही वास्तविक यह कोई जादुई समाधान नहीं है। कमजोर फिल्ट्रेशन, पाइपलाइन जाम, ज्यादा ऑक्सीजन, माइक्रोबियल असंतुलन, खराब रखरखाव, सिस्टम विफल, यह "प्लग-एंड-प्ले" मॉडल नहीं, बल्कि अनुशासन और निगरानी मांगता है।

असली बदलाव: इनपुट नहीं, नियंत्रण

परंपरागत खेती "ज्यादा इनपुट" पर आधारित है - ज्यादा उर्वरक, ज्यादा पानी, ज्यादा एडिटिव्स। यह प्रणाली एक अलग **दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है:** इनपुट की मात्रा नहीं, बल्कि उनके प्रवाह और नियंत्रण पर फोकस

अंतिम सवाल: क्या यह सही समस्या को हल करता है?

यह सवाल नहीं है कि यह प्रणाली परफेक्ट है या नहीं। सवाल यह है कि क्या यह खेती की असली समस्या को संबोधित करती है? और वह समस्या स्पष्ट है - अपशिष्ट उत्पादन और जड़ अवशोषण के बीच नियंत्रण की कमी

यह खेती में कुछ नया जोड़ने के बारे में नहीं है - यह जो पहले से मौजूद है उसे इस तरह जोड़ने के बारे में है कि पौधे तक पहुंचने से पहले कुछ भी बर्बाद न हो।

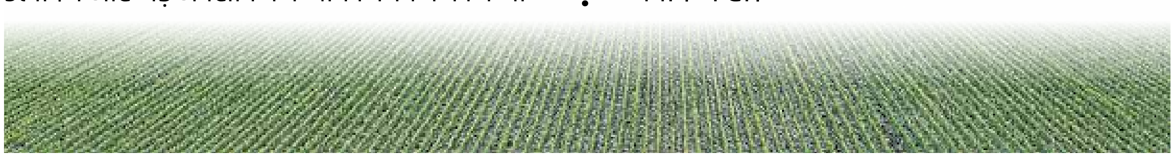

गेहूं के मोर्चे पर बढ़ती दोहरी चुनौती

रफ्तार मीडिया || संवाददाता

भारत में गेहूं केवल एक फसल नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा का आधार है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से लेकर खुले बाजार तक, इसकी उपलब्धता और कीमत सीधे करोड़ों लोगों की थाली से जुड़ी है। ऐसे में जब उत्पादन और सरकारी खरीद—दोनों पर दबाव दिखाई दे, तो यह चिंता कृषि की सीमाओं से बाहर निकलकर व्यापक आर्थिक मुद्दा बन जाती है। रबी विपणन सत्र 2026–27 इसी तरह की दोहरी चुनौती के संकेत दे रहा है। एक तरफ मौसम की मार से उत्पादन अपेक्षा से कम रहने की आशंका है, तो दूसरी ओर सरकारी खरीद भी लक्ष्य से पीछे चल रही है।

उत्पादन : बढ़त के बावजूद लक्ष्य से कम?

2026 में गेहूं उत्पादन को लेकर तस्वीर "सकारात्मक लेकिन अधूरी" दिखती है। उद्योग से जुड़े संगठनों के अनुमानों के अनुसार, इस साल उत्पादन करीब 11.6–11.7 करोड़ टन रह सकता है, जबकि केंद्र सरकार का प्रारंभिक अनुमान 12.21 करोड़ टन के आसपास था। खाद्य मंत्रालय के स्तर पर भी यह संकेत दिया गया है कि वास्तविक उत्पादन 11–12 करोड़ टन के दायरे में रह सकता है। इसका अर्थ यह है कि पिछले साल (करीब 10.9–11 करोड़ टन) की तुलना में उत्पादन बढ़ा है, लेकिन रिकॉर्ड स्तर के दावे तक पहुंचना मुश्किल दिख रहा है

मौसम का असर: तीनहरी मार

1. रबी सीजन में कम वर्षा : सर्दियों में पर्याप्त बारिश नहीं होने से मिट्टी की नमी कम रही। गेहूं की शुरुआती वृद्धि पर इसका सीधा असर पड़ा।

2. ओलावृष्टि और स्थानीय क्षति : कुछ इलाकों में ओलों ने खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया—खासतौर पर उत्तर भारत के हिस्सों में।

3. समय से पहले गर्मी (Early Heat Stress) : मार्च में तापमान तेजी से बढ़ने से 'दाना भरने की अवस्था' प्रभावित हुई। परिणामः दाने छोटे और सिकुड़े, वजन और गुणवत्ता दोनों में गिरावट, यही कारण है कि इस साल चर्चा केवल उत्पादन की नहीं, बल्कि क्वालिटी की भी है।

इस साल गेहूं की फसल पर मौसम ने कई स्तरों पर असर डाला

गुणवत्ता का संकट: मानकों में ढील क्यों?

कमजोर दानों और कम चमक वाली फसल के कारण कई राज्यों में सरकारी खरीद के लिए तय मानकों को पूरा करना मुश्किल हुआ।

इसी वजह से केंद्र और राज्यों ने: गुणवत्ता मानकों में अस्थायी ढील दी, 'नॉन-स्टैंडर्ड' गेहूं की खरीद की अनुमति दी

इसका मकसद था: किसानों को नुकसान से बचाना, सरकारी भंडार के लिए पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना

सरकारी खरीद: लक्ष्य से पीछे चलती मशीनरी

रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए केंद्र ने 345 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया था। लेकिन मई की शुरुआत तक देशभर में खरीद करीब 240 लाख टन के आसपास ही पहुंच पाई - जो पिछले साल इसी समय (~260 लाख टन) से कम है। वर्तमान रुझान बताते हैं कि कुल खरीद 300 लाख टन के आसपास सिमट सकती है। यह अंतर छोटा नहीं है, क्योंकि यही खरीद देश के बफर स्टॉक और PDS की आपूर्ति तय करती है।

राज्यवार तस्वीर: असमान प्रदर्शन

पंजाब और हरियाणा में इस साल भी गेहूं खरीद का पारंपरिक ढांचा अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ दिखता है। पंजाब में अब तक लगभग 110 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जबकि राज्य का लक्ष्य 122 लाख टन रखा गया था। वहीं हरियाणा ने 77 लाख टन से अधिक खरीद के साथ अपने करीब 72 लाख टन के लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया है। यह दर्शाता है कि इन राज्यों में स्थापित खरीद तंत्र, मंडी नेटवर्क और प्रशासनिक दक्षता अभी भी अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसके उलट, मध्य प्रदेश—जो पिछले कुछ वर्षों में गेहूं उत्पादन का उभरता केंद्र बनकर सामने आया था—इस बार सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है। राज्य ने अपना खरीद लक्ष्य 100 लाख टन तक बढ़ाया था, लेकिन अब तक केवल लगभग 29 लाख टन गेहूं की खरीद हो सकी है, जबकि पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा करीब 70 लाख टन था। यानी खरीद आधे से भी कम रह गई है। इसके पीछे केवल उत्पादन में कमी नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक दिक्कतें भी जिम्मेदार रही हैं। किसानों को पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग में परेशानी हुई, खरीद केंद्रों पर देरी और अव्यवस्था की शिकायतें सामने आईं, और कई किसानों ने तत्काल भुगतान के लिए निजी व्यापारियों को प्राथमिकता दी। स्थिति को संभालने के लिए राज्य सरकार को खरीद अवधि बढ़ाने का फैसला करना पड़ा।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी खरीद की रफ्तार उम्मीद से कम रही है, जबकि दोनों राज्यों ने किसानों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिए थे। राजस्थान में एमएसपी के ऊपर बोनस देने के बावजूद अब तक केवल करीब 10 लाख टन गेहूं की खरीद हो सकी है, जो पिछले साल की समान अवधि के लगभग 12 लाख टन से कम है और 25 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले आधी से भी कम है।

इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी खरीद सुस्त रही है—करीब 7.5 लाख टन की खरीद पिछले साल के लगभग 8.1 लाख टन से कम है। यह संकेत देता है कि केवल बोनस या प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं हैं; खरीद तंत्र की दक्षता और किसानों तक उसकी पहुंच उतनी ही महत्वपूर्ण है।

"गेहूं की कहानी अब खेत से आगे बढ़कर मंडी, मौसम और नीति के जटिल संतुलन में लिखी जा रही है।"

नीतिगत संकेत: सिस्टम को क्या सीखना चाहिए?

मौजूदा परिस्थितियां साफ इशारा करती हैं कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; पूरे सिस्टम को अधिक लचीला और कुशल बनाना होगा।

1. खरीद प्रक्रिया का सरलीकरण: डिजिटल पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और खरीद केंद्रों की प्रक्रियाओं को सरल और किसान-हितैषी बनाना जरूरी है। जटिल सिस्टम खरीद की रफ्तार को धीमा करते हैं और किसानों को वैकल्पिक बाजार की ओर धकेलते हैं।

2. गुणवत्ता मानकों में गतिशीलता: मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए गुणवत्ता मानकों में लचीलापन लाना होगा। हर साल एक जैसे मानक लागू करना व्यावहारिक नहीं है, खासकर जब फसल पर जलवायु का असर स्पष्ट हो।

3. क्लाइमेट-रेजिलिएंट खेती: भविष्य की खेती के लिए गर्मी और सूखे को सहन करने वाली किस्मों का विकास, बेहतर सिंचाई प्रबंधन और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना अनिवार्य होता जा रहा है।

4. बाजार-आधारित जोखिम प्रबंधन: किसानों को केवल MSP पर निर्भर रहने के बजाय जोखिम प्रबंधन के आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा।

हेजिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अन्य मार्केट टूल्स के जरिए कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाव संभव है, जो आने वाले समय में कृषि की स्थिरता के लिए अहम साबित होगा।

क्यों घट रही है सरकारी खरीद ?

1. गुणवत्ता का मुद्दा: मौसम की मार के कारण कई इलाकों में गेहूं के दाने कमजोर और सिकुड़े हुए रहे, जिससे वे निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। परिणामस्वरूप, बड़ी मात्रा में फसल या तो सरकारी खरीद से बाहर रह गई या फिर मानकों में ढील देनी पड़ी।

2. निजी खरीद का घटता आकर्षण: अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें नरम रहने से निर्यात के अवसर सीमित रहे। इसका सीधा असर यह हुआ कि निजी व्यापारियों की दिलचस्पी कम हो गई और बाजार में सक्रिय खरीदारी का दबाव घट गया।

3. प्रशासनिक बाधाएं: खासतौर पर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और खरीद केंद्रों की प्रक्रियात्मक जटिलताओं ने खरीद की रफ्तार धीमी कर दी। कई किसान समय पर अपनी फसल बेच नहीं पाए।

4. किसानों की प्राथमिकताएं: जहां MSP पर खरीद में देरी होती है, वहां किसान निजी खरीदारों को प्राथमिकता देते हैं। भले ही कीमत थोड़ी कम मिले, लेकिन तत्काल भुगतान मिलने की सुविधा उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है।

निष्कर्ष : बदलती खेती की नई हकीकत

2026 का गेहूं सीजन एक साफ संकेत दे रहा है - खेती अब सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की कहानी नहीं रही, बल्कि अनिश्चितताओं के साथ समझदारी से खेलना सीखने की जरूरत बन चुकी है। कम पैदावार और सुस्त सरकारी खरीद की यह दोहरी मार बताती है कि पारंपरिक मॉडल अब दबाव में है। बदलते मौसम, अस्थिर बाजार और प्रक्रियात्मक चुनौतियों के बीच टिके रहने के लिए कृषि को अब अधिक लचीला, तकनीक-समर्थ और बाजार-संवेदी बनना ही होगा। फिलहाल सरकार के पास बफर स्टॉक और नीतिगत हस्तक्षेप जैसे तात्कालिक सहारे मौजूद हैं, जो हालात को संभाल सकते हैं। लेकिन असली सवाल आगे का है—क्या व्यवस्था खुद को बदलने के लिए तैयार है? दीर्घकालिक स्थिरता केवल खरीद बढ़ाने या हस्तक्षेप करने से नहीं आएगी, बल्कि संरचनात्मक सुधार, बेहतर प्रबंधन और जलवायु के अनुरूप नई रणनीति अपनाने से ही सुनिश्चित होगी।

क्या उत्पादन के आंकड़े भी सवालों में?

सरकारी खरीद और निजी खरीद - दोनों के कमजोर रुझान एक महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। सवाल उठता है कि क्या इस साल उत्पादन का अनुमान वास्तविकता से अधिक आंका गया था? भले ही अंतिम आंकड़े आने में अभी समय है, लेकिन मौजूदा संकेत कुछ संदेह जरूर पैदा करते हैं। जब एक तरफ सरकारी खरीद लक्ष्य से पीछे रह जाए और दूसरी ओर निजी बाजार में भी अपेक्षित सक्रियता न दिखे, तो यह स्थिति उत्पादन के दावों पर पुनर्विचार की जरूरत की ओर इशारा करती है। ऐसे में कम खरीद और कमजोर बाजार गतिविधि - दोनों मिलकर यह सवाल खड़ा करते हैं कि जमीनी हकीकत और आधिकारिक अनुमान के बीच कहीं अंतर तो नहीं है।

बाजार और महंगाई: आगे क्या?

गेहूं की मौजूदा स्थिति का असर सीधे खाद्य मुद्रास्फीति पर पड़ता है, क्योंकि यह देश की खपत का मुख्य आधार है। उत्पादन में अनिश्चितता और सरकारी खरीद में सुस्ती के संकेत बाजार में धीरे-धीरे दिखाई देने लगते हैं।
संभावित प्रभावः खुले बाजार में गेहूं की कीमतों में क्रमिक बढ़ोतरी, आटा, मैदा और अन्य उत्पादों की लागत में इजाफा, शहरी उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त दबाव, हालांकि फिलहाल सरकार के पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है, जिससे तुरंत बड़े झटके को संभाला जा सकता है। लेकिन यदि लगातार दो सीजन तक उत्पादन और खरीद दोनों दबाव में रहते हैं, तो यह संतुलन बिगड़ सकता है और कीमतों पर व्यापक असर देखने को मिल सकता है।

शुगर से एनर्जी तक बदलता सेक्टर

60 साल पुराने कानून को बदलने की तैयारी सिर्फ एक प्रशासनिक अपडेट नहीं है। यह संकेत है कि भारत का शुगर सेक्टर अब "चीनी उत्पादन" से आगे बढ़कर "बायो-एनर्जी इकोनॉमी" की ओर कदम रख रहा है—जहां गन्ना सिर्फ फसल नहीं, बल्कि मल्टी-प्रोडक्ट एसेट बन चुका है। भारतीय शुगर सेक्टर लंबे समय से एक सख्त नियामकीय ढांचे के तहत काम करता रहा है। Cane Control Order 1966 ने दशकों तक किसानों, मिलों और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम तेज़ी से बढ़ रहा है ऊर्जा सुरक्षा और आय की विविधता प्राथमिकता बन चुके हैं। मिलें अब केवल चीनी नहीं, बल्कि कई उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं ऐसे में सरकार ने Cane Control Order 2026 (ड्राफ्ट) जारी कर इस सेक्टर को नए ढांचे में ढालने की पहल की है। पुराने नियम, जस के तस-किसानों के लिए सुरक्षा बरकरार : ड्राफ्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 दिनों में भुगतान का नियम देरी पर 15% ब्याज डिफाल्टर मिलों पर कार्रवाई इन सभी प्रावधानों को बिना बदलाव जारी रखा गया है। यह संकेत है कि सरकार सुधारों के बीच किसानों की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहती।

क्या बदलेगा : पांच बड़े बदलाव जो तय करेंगे भविष्य

1. मिलों के बीच दूरी: 15 से 25 किलोमीटर अब एक चीनी मिल के 25 किलोमीटर दायरे में दूसरी मिल नहीं लग सकेगी।

क्या मतलब है? : मिलों को गन्ना खरीदने के लिए बड़ा क्षेत्र मिलेगा। ओवर-कम्पटीशन और कच्चे माल की खींचतान कम होगी। पर्यावरणीय दबाव भी घट सकता है। इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में दिखेगा

2. राज्यों को मिली ज्यादा ताकत : नई मिल लगाने या क्षमता बढ़ाने के लिए अब केंद्र की मंजूरी जरूरी नहीं होगी।

परिणाम: राज्यों की भूमिका बढ़ेगी, निवेश फैसले तेज होंगे, क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है

3. खांडसारी यूनिट्स की एंट्री पहली बार खांडसारी (छोटी) इकाइयों को "इथेनॉल इंडस्ट्री" का हिस्सा बनाया गया है। इससे छोटे उत्पादकों को नई पहचान, गुड़ आधारित एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा, ग्रामीण स्तर पर वैल्यू एडिशन

4. एथेनॉल : चीनी (नई इकॉनमी का संकेत) ड्राफ्ट में पहली बार एथेनॉल को चीनी के बराबर दर्जा दिया गया है।

अब: 600 लीटर एथेनॉल = 1 टन चीनी गन्ने का रस, शीरा, सिरप - ये सभी आउटपुट माने जाते हैं।

यह बदलाव क्या कहता है? शुगर मिल अब "शुगर फैक्ट्री" नहीं, बल्कि "बायो-एनर्जी हब" बनेंगी

5. FRP का नया फॉर्मूला : अब गन्ने की कीमत तय करते समय सिर्फ चीनी रिकवरी नहीं, बल्कि शीरा, बगास, और एथेनॉल - इन सभी का मूल्य भी जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को बेहतर रिटर्न मिलने का रास्ता खुल सकता है

> **"गन्ना अब सिर्फ चीनी का स्रोत नहीं रहा—यह ऊर्जा, एथेनॉल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया इंजन बनता जा रहा है।"**

> **"अब सवाल सिर्फ चीनी उत्पादन का नहीं है—सवाल यह है कि गन्ने से कितनी वैल्यू निकाली जा सकती है।"**

निष्कर्ष: नई नीति, नया संतुलन

Cane Control Order 2026 केवल नियमों का एक साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत की कृषि, खासकर गन्ना सेक्टर, धीरे-धीरे कमोडिटी आधारित ढांचे से निकलकर वैल्यू-ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में यही बदलाव तय करेगा कि क्या किसान बेहतर और स्थिर आय हासिल कर पाएंगे, क्या चीनी मिलें एक टिकाऊ और विविधीकृत बिज़नेस मॉडल विकसित कर सकेंगी, और क्या भारत एथेनॉल व बायो-एनर्जी के सहारे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ पाएगा।

क्या बदलेगा जमीन पर?

किसान अब मिल की दूरी से बंधा रहेगा मिलें गन्ने की बजाय "एथेनॉल वैल्यू" पर ज्यादा ध्यान देंगी। खांडसारी यूनिट्स ग्रामीण स्तर पर नया बिज़नेस मॉडल बन सकती हैं।

क्या जोखिम भी हैं?

कम प्रतिस्पर्धा किसानों के विकल्प घट सकते हैं। राज्यों को अधिक अधिकार पॉलिसी मिसमैच का खतरा, एथेनॉल पर ज्यादा निर्भरता शुगर मार्केट में अस्थिरता

फ्यूचर आउटलुक : आगे क्या?

अगर यह ड्राफ्ट लागू होता है, तो अगले 5 साल में: शुगर मिल। "इंटीग्रेटेड बायो-रिफाइनरी" बन सकती हैं| किसान। केवल गन्ना उत्पादक नहीं, वैल्यू चेन का हिस्सा बनेंगे| भारत। एथेनॉल आधारित ऊर्जा मॉडल में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है

शुगर सेक्टर : एक नज़र में

भारत: दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक	
एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य	: 20%
गन्ना किसानों की संख्या:	~5 करोड़
मिलों की संख्या:	500+
एथेनॉल क्षमता:	तेज़ी से बढ़ती हुई

किस पर क्या असर? - पूरा समीकरण समझिए

किसान: फायदा या चुनौती?

नए प्रस्तावित ढांचे में किसानों के लिए एक तरफ बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ती दिखती है, क्योंकि गन्ने के मूल्य निर्धारण में अब एथेनॉल, शीरा और अन्य उप-उत्पादों की वैल्यू भी शामिल की जा सकती है। साथ ही, 14 दिनों में भुगतान और देरी पर ब्याज जैसे प्रावधान जस के तस रखे गए हैं, जिससे भुगतान सुरक्षा बनी रहती है।

हालांकि, मिलों के बीच दूरी बढ़ाकर 25 किलोमीटर किए जाने से किसानों के विकल्प कुछ सीमित हो सकते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा घटने और सौदेबाजी की ताकत पर असर पड़ने की आशंका भी बनी रहती है।

चीनी मिलें: नया बिज़नेस मॉडल

नए ढांचे में चीनी मिलों के लिए बिज़नेस मॉडल तेजी से बदलता दिख रहा है, जहां एथेनॉल उत्पादन के जरिए अतिरिक्त आय के नए स्रोत खुल रहे हैं। अब मिलें केवल चीनी पर निर्भर रहने के बजाय मल्टी-प्रोडक्ट मॉडल - जैसे एथेनॉल, बगास और शीरा - की ओर बढ़ रही हैं, जिससे उनकी आय में स्थिरता आ सकती है।

हालांकि, मिलों के बीच दूरी बढ़ने से प्रतिस्पर्धा कम होने की आशंका भी है, जो लंबे समय में दक्षता और लागत नियंत्रण पर असर डाल सकती है।

छोटे उद्योग (खांडसारी) : नए प्रस्तावित ढांचे में खांडसारी इकाइयों को पहली बार औपचारिक मान्यता मिलती दिख रही है, जो इनके लिए एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। अब इन्हें एथेनॉल इंडस्ट्री का हिस्सा बनाकर वैल्यू चेन में शामिल किया जा रहा है, जिससे छोटे उत्पादकों के लिए नए अवसर खुलेंगे और ग्रामीण स्तर पर वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिल सकता है।

राज्य सरकारें : नए ढांचे में राज्य सरकारों की भूमिका पहले के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत होती दिख रही है, क्योंकि नई मिलों की स्थापना और क्षमता विस्तार जैसे फैसले अब राज्य स्तर पर ही लिए जा सकेंगे। इससे राज्यों को निवेश आकर्षित करने और स्थानीय स्तर पर सेक्टर के विकास को गति देने का अवसर मिलेगा।

हालांकि, इसके साथ ही नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाएगी, जो प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा ले सकती है।

बड़ा बदलाव: "शुगर सेक्टर" से "बायो-इकोनॉमी" की ओर यह ड्राफ्ट एक गहरे बदलाव का संकेत देता है।

पहले: फोकस : चीनी उत्पादन

अब: फोकस = ऊर्जा + वैल्यू एडिशन + विविध राजस्व कुल मिलाकर, गन्ना अब सिर्फ "मीठी फसल" नहीं, बल्कि फ्यूल, पावर और इंडस्ट्रियल इनपुट का स्रोत बन रहा है । चुनौतियां भी कम नहीं हालांकि तस्वीर पूरी तरह आसान नहीं है: भुगतान अनुशासन लागू करना, एथेनॉल नीति की स्थिरता, छोटे और बड़े खिलाड़ियों के बीच संतुलन क्षेत्रीय असमानताएं, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो सुधार अधूरे रह सकते हैं।

ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और भारत का दांव

रफ्तार मीडिया || संवाददाता

इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे 2026 के संघर्ष को आमतौर पर परमाणु तनाव और क्षेत्रीय दुश्मनी के चश्मे से देखा जा रहा है। लेकिन सतह के नीचे एक कहीं बड़ा और जटिल बदलाव आकार ले रहा है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है - यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के "कंट्रोल रूम" पर पकड़ मजबूत करने की लड़ाई है। जो दृश्य सामने दिख रहा है, वह तबाही का है; लेकिन इसके पीछे छिपी प्रक्रिया दुनिया की ऊर्जा जीवनरेखाओं पर नियंत्रण के पुनर्गठन की कहानी कहती है।

होर्मुज़ से भूमध्य तक: ऊर्जा के 'चोक पॉइंट्स'

इस पूरे बदलाव के केंद्र में है होर्मुज जलडमरूमध्य - एक ऐसा संकरा समुद्री मार्ग, जिससे होकर हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुज़रता है। इस पर ईरान का प्रभाव उसे वैश्विक ऊर्जा प्रवाह पर असाधारण रणनीतिक बढ़त देता है। यहां किसी भी तरह की रुकावट का असर तुरंत वैश्विक तेल बाज़ार, शिपिंग मार्गों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। लेकिन यह कहानी केवल होर्मुज़ तक सीमित नहीं है। पश्चिम की ओर, इज़राइल का इलियट-एशकेलोन पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एक वैकल्पिक ऊर्जा गलियारा प्रदान करता है। दोनों को साथ रखें, तो यह एक दोहरी 'चोक पॉइंट' प्रणाली बनती है -जहां एक प्रवेश को नियंत्रित करता है और दूसरा निकास को। यह कोई सैद्धांतिक कल्पना नहीं, बल्कि भूगोल और इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा निर्मित एक ठोस वास्तविकता है।

लाल सागर की अस्थिरता

पारंपरिक मार्गों पर दबाव

इस समीकरण को और जटिल बनाता है बाब अल-मन्देब जलसन्धि, जो लाल सागर को वैश्विक शिपिंग मार्गों से जोड़ता है। हाल के वर्षों में क्षेत्रीय संघर्षों और व्यापारिक जहाजों पर हमलों के कारण यह मार्ग लगातार अस्थिर होता जा रहा है। यहां तक कि जब तेल सऊदी अरब की पाइपलाइनों के जरिए होर्मुज को बाईपास करता है, तब भी उसे इस क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। नतीजाः लाल सागर का मार्ग अविश्वसनीय होता जा रहा है और इज़राइल के जरिए भूमध्य सागर तक पहुंचने वाले वैकल्पिक मार्ग का महत्व तेजी से बढ़ रहा है।

इतिहास का पैटर्न

दुश्मनी के बीच सहयोग

यह स्थिति पूरी तरह नई नहीं है। इतिहास बताता है कि भू-राजनीति में सार्वजनिक बयान और वास्तविक रणनीति अक्सर अलग-अलग रास्तों पर चलते हैं। 1979 से पहले, ईरान और इज़राइल रणनीतिक साझेदार थे - ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और खुफिया सहयोग में। यहां तक कि वैचारिक टकराव शुरू होने के बाद भी, पर्दे के पीछे संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुए। हथियारों का लेन-देन और सीमित समन्वय समय-समय पर जारी रहा। इससे एक पैटर्न स्पष्ट होता हैः देश सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं, लेकिन जब आर्थिक और रणनीतिक हित सामने होते हैं, तो सहयोग के रास्ते खुलते रहते हैं।

समय का संयोग या रणनीतिक बदलाव?

मौजूदा परिदृश्य को जो चीज सबसे अलग बनाती है, वह है इसका समय। संयुक्त राज्य अमेरिका अब खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा का अकेला गारंटर बने रहने को लेकर पहले जितना प्रतिबद्ध नहीं दिखता। ईरान आंतरिक आर्थिक दबाव और पुनर्निर्माण की जरूरत से जूझ रहा है। इज़राइल भी लगातार सैन्य तनाव से आगे बढ़कर एक स्थिर, दीर्घकालिक सुरक्षा ढांचा चाहता है। इसी बीच, वैश्विक बाज़ार तेजी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं - तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं और सप्लाई चेन दबाव में हैं। ये घटनाएं अलग-अलग नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव के संकेत हैं - एक नई ऊर्जा व्यवस्था के उभरने के।

नई व्यवस्था: सहयोग या नियंत्रण?

अगर यह उभरती व्यवस्था, भले ही अनौपचारिक रूप में, आकार लेती है, तो इसके आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव व्यापक होंगे। एक संभावित संयुक्त ऊर्जा गलियारा ढांचा सालाना 15 से 25 अरब डॉलर तक का राजस्व उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब यह होगा कि ईरान और इज़राइल दोनों वैश्विक ऊर्जा प्रवाह के "गेटकीपर" बन सकते हैं। यहीं से एक असहज लेकिन ज़रूरी सवाल उठता हैः अगर इस पुनर्गठित व्यवस्था से दोनों पक्षों को लाभ मिल सकता है, तो क्या यह संघर्ष पूरी तरह विनाशकारी है या फिर इसका एक हिस्सा उस बदलाव का चरण है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से गढ़ रहा है?

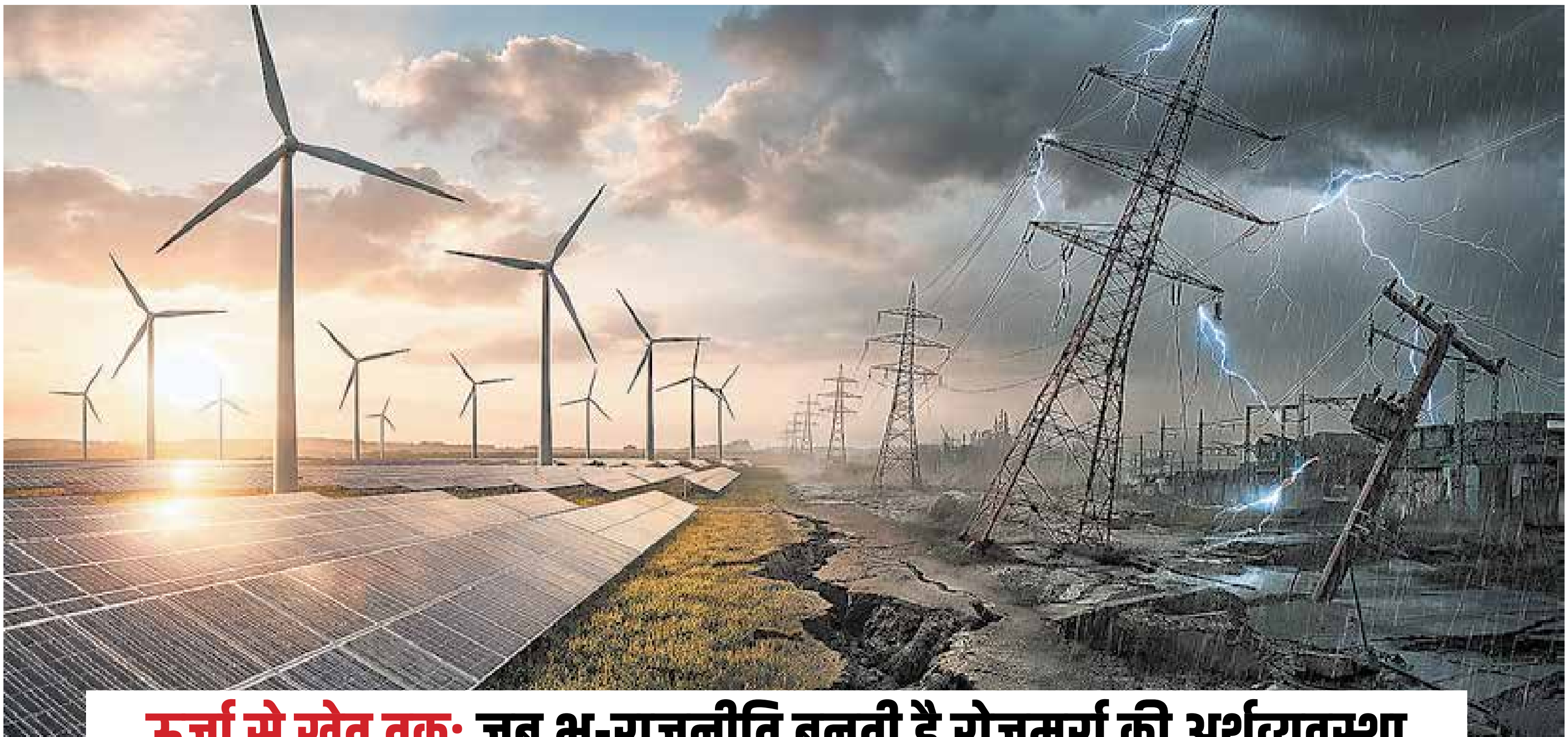

ऊर्जा से खेत तक: जब भू-राजनीति बनती है रोज़मर्रा की अर्थव्यवस्था

इस बदलाव का असर अब एक ऐसे क्षेत्र में साफ दिखाई देने लगा है, जिसे भू-राजनीतिक विश्लेषण में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है - कृषि। भारत के लिए यह जुड़ाव सीधा और तत्काल है। उर्वरक (खाद) बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम इनपुट पर निर्भर करते हैं। सिंचाई, परिवहन और खेती की मशीनरी डीज़ल से संचालित होती है। कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी, पूरे भारत में कृषि इनपुट लागत में एक "खामोश लेकिन गहरा" इज़ाफा करती है।

लागत का दबाव किसान की जेब पर सीधा असर

हाल के व्यवधानों के दौरान फर्टिलाइज़र की कीमतें 40–50% तक बढ़ चुकी हैं। डीजल महंगा होने से प्रति एकड़ सिंचाई लागत बढ़ी है, जबकि परिवहन खर्च ने किसानों के मुनाफ़े को और कम कर दिया है। भारतीय किसानों के लिए यह कोई दूर की भू-राजनीति नहीं - यह एक सीधा आर्थिक दबाव है, जो उनकी आय और अस्तित्व दोनों को प्रभावित करता है। इसका असर गांवों तक सीमित नहीं रहता। यही दबाव खाद्य मुद्रास्फीति के रूप में शहरों तक पहुंचता है, जहां रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऊर्जा संकट से खाद्य सुरक्षा तकः एक सीधी कड़ी यहीं पर ऊर्जा संघर्ष, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। ऊर्जा की अस्थिरता कृषि लागत में अस्थिरता कृषि अस्थिरता राष्ट्रीय आर्थिक तनाव यदि एक स्थिर ऊर्जा कॉरिडोर प्रणाली उभरती है - जो होर्मुज जलडमरूमध्य से लेकर भूमध्य सागर तक जुड़ती हो - तो यह केवल तेल आपूर्ति ही नहीं, बल्कि उर्वरक उपलब्धता और कृषि लागत को भी स्थिर कर सकती है। व्यावहारिक रूप से, इसका अर्थ हैः ऊर्जा स्थिरता ही खाद्य सुरक्षा की बुनियाद बन सकती है।

भारत की रणनीतिक स्थिति: संतुलन से अवसर तक

इस उभरते परिदृश्य में भारत की स्थिति विशिष्ट रूप से रणनीतिक है। भारत उन चुनिंदा देशों में है, जो ईरान और इज़राइल - दोनों के साथ कार्यात्मक संबंध बनाए हुए हैं। ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश और इज़राइल के साथ गहरे तकनीकी सहयोग के जरिए भारत पहले से ही इस उभरते ऊर्जा कॉरिडोर के दोनों सिरों पर मौजूद है। यह स्थिति भारत को एक निष्क्रिय उपभोक्ता से आगे बढ़ाकर - एक संभावित "केंद्रीय खिलाड़ी" बनने का अवसर देती है।

लॉजिस्टिक्स का दबाव : अदृश्य लेकिन निर्णायक

ऊर्जा संकट का एक बड़ा पहलू लॉजिस्टिक्स भी है। शिपिंग मार्ग अब संघर्ष के बढ़ते जोखिम में हैं, युद्ध बीमा प्रीमियम लगातार बढ़ रहे हैं और माल ढुलाई की लागत तेज़ी से ऊपर जा रही है, जिससे कुल आपूर्ति और महंगाई पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। भले ही तेल उपलब्ध हो, लेकिन उसे सुरक्षित और सस्ते तरीके से पहुंचाना अब एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनता जा रहा है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है, खासतौर पर भारत जैसी आयात-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में

रणनीतिक अवसर भारत क्या कर सकता है?

भारत, ओमान जैसे तटस्थ मध्यस्थों के माध्यम से ईरान, इज़राइल और खाड़ी देशों को शामिल करते हुए एक संरचित संवाद शुरू कर सकता है।
साथ हीः

- ईरान के साथ दीर्घकालिक उर्वरक और कच्चे तेल की आपूर्ति समझौते
- इज़राइल के साथ कृषि और जल प्रौद्योगिकी साझेदारी का विस्तार

यह भारत को ऊर्जा सुरक्षा और कृषि स्थिरता—दोनों में लाभ दे सकता है।
एक नया एकीकरण मॉडलः ऊर्जा + तकनीक + कृषि
इस उभरते समीकरण में एक स्पष्ट संरचना दिखाई देती हैः

- ईरान ऊर्जा और उर्वरक
- इज़राइल उन्नत कृषि और जल तकनीक
- भारत कार्यान्वयन और बाजार

यह केवल कूटनीति नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक आर्थिक मॉडल है - जो भारत की महंगाई, मुद्रा स्थिरता और कृषि लचीलापन को सीधे प्रभावित कर सकता है।

डॉलर से परे : बदलता ऊर्जा व्यापार

इस पूरी प्रक्रिया के साथ एक बड़ा वित्तीय बदलाव भी संभव है। जैसे-जैसे पारंपरिक ऊर्जा मार्ग अस्थिर होते जा रहे हैं, देश डॉलर-आधारित तेल व्यापार के विकल्प तलाश रहे हैं। ईरान पहले ही गैर-डॉलर निपटान के पक्ष में रहा है, जबकि भारत ने रुपये-आधारित व्यापार तंत्र पर प्रयोग किए हैं। यदि नए ऊर्जा कॉरिडोर पारंपरिक पश्चिमी नियंत्रण से बाहर संचालित होते हैं, तो वैश्विक तेल व्यापार में डॉलर का वर्चस्व धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है।

बदलता वैश्विक शक्ति संतुलन

इस पूरे घटनाक्रम के बीच वैश्विक शक्ति संतुलन भी बदल रहा है। चीन, जो मध्य-पूर्व के तेल पर काफी निर्भर है, एक रणनीतिक दुविधा में है। उसे ऊर्जा प्रवाह में स्थिरता चाहिए, लेकिन इज़राइल से जुड़े किसी भी गठबंधन को लेकर वह राजनीतिक रूप से सतर्क रहता है। इससे एक दोहरी स्थिति बनती है, जहां चीन परोक्ष रूप से स्थिरता का समर्थन करता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से दूरी बनाए रखता है। खाड़ी देश, विशेष रूप से सऊदी अरब, भी ईरान और इज़राइल दोनों के प्रभाव वाले किसी तंत्र पर निर्भर होने को लेकर सावधानी बरतते हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की पारंपरिक "वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा गारंटर" की भूमिका भी धीरे-धीरे कमज़ोर होती दिख रही है।

सीमाएं और सच्चाई: खुला सहयोग अभी दूर

ईरान और इज़राइल - दोनों के भीतर घरेलू विरोध अभी भी मज़बूत है। वैचारिक टकराव, राजनीतिक मजबूरियाँ और संस्थागत दबाव खुले सहयोग की संभावनाओं को सीमित करते हैं। अगर कोई समझौता या गठबंधन बनता भी है, तो वह संभवतः खुले मंच पर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे तैयार होगा—मध्यस्थ देशों, तटस्थ वित्तीय ढाँचों और अनौपचारिक चैनलों के जरिए। औपचारिक कूटनीति के बजाय, खुफिया एजेंसियाँ और सुरक्षा प्रतिष्ठान इस तरह की व्यवस्थाओं को आकार देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

विफलता का जोखिम: कीमत कितनी भारी हो सकती है

इस पूरी प्रक्रिया में जोखिम भी उतना ही बड़ा है। अगर यह पुनर्गठन साकार नहीं होता, तो Strait of Hormuz में बनी रहने वाली अस्थिरता तेल की कीमतों को 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँचा सकती है। इसका असर केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहेगा—यह वैश्विक महंगाई और आर्थिक मंदी को भी जन्म दे सकता है।

यह युद्ध नहीं, व्यवस्था का पुनर्निर्माण है

यह केवल एक युद्ध नहीं है जो लड़ा जा रहा है। यह एक ऐसी व्यवस्था का पुनर्निर्माण है - जहाँ ऊर्जा मार्गों पर नियंत्रण ही आर्थिक शक्ति को परिभाषित करेगा, खाद्य सुरक्षा को आकार देगा और भारत जैसे देशों के भविष्य की स्थिरता तय करेगा।

भारत के लिए इसका मतलब होगा

भारत के लिए इसका मतलब होगा ईंधन की ऊँची कीमतें, खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम और उर्वरक सब्सिडी पर बढ़ता राजकोषीय दबाव। यह जोखिम सैद्धांतिक नहीं, बल्कि तत्काल और स्पष्ट रूप से मापने योग्य है।

ऊर्जा से पानी तक: सहयोग का अगला चरण

इस पूरे समीकरण का एक दीर्घकालिक पर्यावरणीय पहलू भी है। ईरान गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, जबकि इज़राइल जल प्रबंधन और डीसैलिनेशन (समुद्री पानी को मीठा बनाने) की तकनीकों में अग्रणी है। अगर ऊर्जा आधारित सहयोग आगे बढ़ता है, तो यह धीरे-धीरे पानी और कृषि के क्षेत्र में साझेदारी का रूप ले सकता है, जो पूरे क्षेत्र की जलवायु और संसाधन संबंधी चुनौतियों को कम करने में मदद करेगा। यह बदलाव "टकराव के प्रबंधन" से आगे बढ़कर "अस्तित्व की रणनीति" का रूप ले सकता है।

सत्ता का नया गणित

रास्तों पर तय होगा भविष्य

सबसे बड़ा बदलाव वैश्विक सत्ता के बँटवारे में हो रहा है। ऊर्जा गलियारों पर नियंत्रण अब शक्ति का सबसे निर्णायक कारक बनता जा रहा है। भविष्य की वैश्विक शक्ति केवल वॉशिंगटन या बीजिंग में तय नहीं होगी - बल्कि उन मार्गों पर तय होगी, जो खाड़ी क्षेत्र को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं।

भारत के लिए दांव: सिर्फ कूटनीति नहीं, अस्तित्व का सवाल

भारत के लिए यह केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि कृषि आधार को सुरक्षित रखने, महंगाई को नियंत्रित करने और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह तय करने का सवाल है। आज लिए गए फैसले ही यह निर्धारित करेंगे कि भारत बाहरी झटकों के प्रति कमजोर बना रहता है या एक अधिक स्थिर वैश्विक व्यवस्था का सक्रिय निर्माता बनकर उभरता है।

आम नागरिक तक असर

अदृश्य से प्रत्यक्ष

इस पूरे घटनाक्रम का असर अंततः आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखेगा—ईंधन की कीमतों में बदलाव, खाने-पीने की चीजों की बढ़ती लागत और आर्थिक सुरक्षा की भावना पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में। नीति-निर्माताओं के लिए चुनौती यह है कि इसे केवल एक दूरस्थ संघर्ष के रूप में न देखें, बल्कि एक ऐसे व्यापक बदलाव के रूप में समझें, जिसमें सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

वैज्ञानिक तरीके से तुड़ाई करें

आम की-स्वाद भी बढ़े, दाम भी!

रफ्तार मीडिया || संवाददाता

मई की गर्म सुबह हो या जून की उमस भरी दोपहर—आम के बागों में इन दिनों रौनक अलग ही होती है। पेड़ों पर लदे फलों को देखकर किसान की मेहनत नजर आती है, लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। क्योंकि आम की खेती में सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि तुड़ाई और उसके बाद का प्रबंधन तय करता है कि फल बाजार में कितना टिकेगा और कितनी कीमत लाएगा। आम की तुड़ाई कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पूरी वैज्ञानिक श्रृंखला है-जहां हर कदम गुणवत्ता और मुनाफे को प्रभावित करता है। आम (Mangifera indica L.) को 'फलों का राजा' कहा जाता है—और यह केवल स्वाद के कारण नहीं, बल्कि इसकी आर्थिक अहमियत भी उतनी ही बड़ी है। विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह फल देश-विदेश दोनों बाजारों में मांग में रहता है। भारत दुनिया का अग्रणी आम उत्पादक है, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख राज्य हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर नजरअंदाज हो जाता है—कटाई और भंडारण के दौरान 25 से 40 प्रतिशत तक नुकसान। यानी, खेत में पैदा हुआ हर फल सुरक्षित रूप से बाजार तक नहीं पहुंच पाता।

तुड़ाई से पहले की तैयारी-छोटे कदम, बड़ा असर

अच्छी तुड़ाई की शुरुआत खेत से ही होती है। तुड़ाई से 10–15 दिन पहले सिंचाई रोक देने से फल में मिठास बढ़ती है और गुणवत्ता बेहतर होती है। इसी तरह, इस समय उर्वरकों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फल जल्दी खराब हो सकता है। रोग और कीट नियंत्रण भी बेहद जरूरी है। तुड़ाई से कुछ सप्ताह पहले उपयुक्त फफूंदनाशी का छिड़काव एन्थ्रेक्नोज और स्टेम एंड रॉट जैसे रोगों से बचाता है, जबकि फल मक्खी के नियंत्रण के लिए ट्रैप और स्वच्छता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

परिपक्वता की सही पहचान-यहीं से तय होती है गुणवत्ता

कई बार किसान जल्दी में कच्चे फल तोड़ लेते हैं या देर कर देते हैं, जिससे स्वाद और शेल्फ लाइफ दोनों प्रभावित होते हैं। सही समय पर तुड़ाई ही अच्छे आम की पहचान है। जब डंठल के पास का हिस्सा भरकर उभरा दिखे, गहरे हरे रंग में हल्का पीलापन आने लगे और फल का गूदा ठोस महसूस हो-तब आम तुड़ाई के लिए तैयार माना जाता है। कई अनुभवी किसान पानी में डुबोकर भी जांच करते हैं; परिपक्व फल डूब जाता है, जबकि कच्चा तैरता है। अब आधुनिक तकनीकों में ड्राई मैटर (लगभग 14–18 प्रतिशत) मापकर भी परिपक्वता तय की जा रही है, जो खासकर निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है।

तुड़ाई के बाद—तापमान पर नियंत्रण जरूरी

तुड़ाई के तुरंत बाद फल में 'फील्ड हीट' रहती है, जिससे उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है और वह जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए तुड़ाई के बाद फलों को तुरंत छायादार स्थान पर रखना चाहिए। आधुनिक स्तर पर प्री-कूलिंग तकनीकों-जैसे हाइड्रो-कूलिंग या फोर्स्ड एयर कूलिंग—का उपयोग किया जा रहा है। तापमान को 12–15C तक लाने से शेल्फ लाइफ में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

तुड़ाई की विधि—सावधानी ही लाभ है

आम की तुड़ाई जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सावधानी से करनी चाहिए। सुबह या शाम के समय तुड़ाई करने से फल को गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। एक ही पेड़ से फल एक बार में नहीं, बल्कि 2-3 चरणों में तोड़ना बेहतर रहता है, क्योंकि सभी फल एक साथ नहीं पकते। तुड़ाई के लिए नायलॉन जाल वाले उपकरण या कैंची का उपयोग करना चाहिए, ताकि फल गिरकर चोटिल न हो। फल को 8-10 सेमी डंठल सहित तोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि इससे निकलने वाला दूधिया स्राव (लेटेक्स) फल पर नहीं गिरता और धब्बे नहीं पड़ते।

जानकारी से बढ़ेगी आमदनी

आम की तुड़ाई केवल फल तोड़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पूरी वैज्ञानिक श्रृंखला है। सही परिपक्वता, सावधानीपूर्वक तुड़ाई, वैज्ञानिक उपचार और उचित भंडारण—इन सबका सीधा असर गुणवत्ता और कीमत पर पड़ता है। आज के बदलते जलवायु परिदृश्य में, जहां असमय बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव आम हो गया है, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। कुलमिलाकर, सही समय, सही तकनीक और वैज्ञानिक सोच—यही है उच्च गुणवत्ता वाले आम उत्पादन की असली पहचान।

भंडारण और बाजार—यहीं से बढ़ती है कमाई

सही भंडारण से ही किसान को बेहतर दाम मिलता है। आम को 12-14°C तापमान और 85-90 प्रतिशत आर्द्रता पर रखना सबसे उपयुक्त माना जाता है। वेंटिलेटेड कार्टन बॉक्स और कुशनिंग सामग्री से पैकिंग करने पर फल सुरक्षित रहता है। कोल्ड चेन का पालन करने से कटाई से बाजार तक नुकसान 20-30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। हाल के वर्षों में एलोवेरा या चिटोसैन आधारित एडिबल कोटिंग का उपयोग भी बढ़ा है, जो फल की नमी बनाए रखता है।

रोग प्रबंधन—नुकसान से बचने की कुंजी

कटाई के बाद रोगों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर एन्थ्रेक्नोज और स्टेम एंड रॉट जैसे रोग। ये फल को तेजी से खराब कर सकते हैं। इससे बचाव के लिए फलों को साफ पानी से धोना, नियंत्रित तापमान पर गर्म पानी उपचार देना और आवश्यकता अनुसार अनुशंसित फफूंदनाशी का प्रयोग करना प्रभावी उपाय हैं। जैविक विकल्पों में ट्राइकोडर्मा आधारित उत्पाद भी तेजी से अपनाए जा रहे हैं।

समान पकाव—सुरक्षित तरीका अपनाएं

बाजार में आकर्षक दिखने के लिए फल का समान रूप से पकना जरूरी है। इसके लिए इथरेल जैसे सुरक्षित रसायन का नियंत्रित उपयोग किया जा सकता है या फिर नियंत्रित पकाव कक्ष का उपयोग किया जाता है, जहां तापमान और आर्द्रता नियंत्रित रहती है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण पूरी तरह प्रतिबंधित है और इससे बचना ही चाहिए।

प्रो. (डॉ.) एस. के. सिंह, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में प्लांट पैथोलॉजी एवं नेमेटोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। पौध रोग विज्ञान और मृदा सूक्ष्मजीविकी के क्षेत्र में उनका दीर्घ अनुभव रहा है, और वे जैव नियंत्रण तथा सतत कृषि के प्रमुख विशेषज्ञों में गिने जाते हैं।

कभी खेती में बदलाव के सबसे बड़े वाहक माने जाने वाले KVK आज स्टाफ की कमी, कमजोर ढांचे और पुरानी कार्यप्रणालियों से जूझ रहे हैं। सवाल यह है—क्या भारत की कृषि व्यवस्था अपने सबसे अहम जमीनी नेटवर्क को धीरे-धीरे खो रही है?

सोए हुए दिग्गज बदलती खेती के दौर में क्यों पिछड़ रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र?

रफ्तार मीडिया || संवाददाता

जब 1960 के दशक में भारत ने हरित क्रांति की नींव रखी, तब एक सपना भी देखा गया था—ऐसी संस्थाओं का, जो कृषि विज्ञान को प्रयोगशालाओं से निकालकर सीधे किसानों के खेत तक पहुंचाएं। इन्हें नाम मिला—कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)। आज देश में 700 से अधिक KVK हैं, लेकिन बदलते कृषि परिदृश्य में क्या वे अब भी किसानों के सबसे भरोसेमंद साथी हैं, या धीरे-धीरे एक औपचारिक सरकारी ढांचे में सिमटते जा रहे हैं? मध्य बिहार का एक किसान मोबाइल पर मौसम का पूर्वानुमान देख रहा है।

पंजाब का किसान यूट्यूब पर पराली प्रबंधन की नई तकनीक समझ रहा है। हिमाचल का बागवान व्हाट्सऐप पर सेब की बीमारी की तस्वीर भेजकर सलाह मांग रहा है। और इसी समय देश के कई कृषि विज्ञान केंद्रों में पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं—जहां किसान कम और खाली कुर्सियां ज्यादा दिखाई देती हैं। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि भारत की कृषि विस्तार प्रणाली का बदलता सच है। कभी गांवों में आधुनिक खेती की सबसे बड़ी पहचान माने जाने वाले कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) आज दो अलग-अलग तस्वीरों के बीच खड़े हैं। एक तरफ वे केंद्र हैं, जिन्होंने खेती की दिशा बदल दी; दूसरी तरफ वे KVK हैं, जो धीरे-धीरे औपचारिक सरकारी संस्थानों में बदलते जा रहे हैं।

एक सपना, जिसने हरित क्रांति को खेत तक पहुंचाया

1960 और 70 के दशक में भारत खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। नई किस्में, सिंचाई और उर्वरकों के साथ यह समझ भी बनी कि विज्ञान को खेत तक पहुंचाने वाली मजबूत व्यवस्था चाहिए। इसी सोच से KVK की अवधारणा सामने आई। इनका उद्देश्य था - किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, नई तकनीकों का खेत स्तर पर परीक्षण करना और वैज्ञानिकों तथा किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना। 1970 के दशक में पहला KVK स्थापित हुआ। धीरे-धीरे यह नेटवर्क पूरे देश में फैल गया। आज लगभग हर जिले में KVK मौजूद है। कागज पर यह भारत की सबसे बड़ी कृषि विस्तार प्रणाली दिखाई देती है, लेकिन पांच दशक बाद सवाल यह है कि क्या यह ढांचा समय के साथ खुद को बदल पाया?

"अगर KVK नहीं बदले, तो किसान विज्ञान से नहीं, सोशल मीडिया से खेती सीखेंगे।"

जहां KVK ने बदली खेती की तस्वीर

कहानी पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। देश के कई हिस्सों में KVK आज भी यह साबित कर रहे हैं कि अगर विज्ञान जमीन से जुड़ जाए, तो खेती की दिशा बदल सकती है।

महाराष्ट्र : चारे से कम्पोस्ट तक बदलाव

बारामती, महाराष्ट्र में KVK ने साइलेज तकनीक को बढ़ावा दिया। पहले हर गर्मी में डेयरी किसानों का चारा खराब हो जाता था और दूध उत्पादन गिर जाता था। अब किसान चारे को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित कर सालभर उपयोग कर रहे हैं। इससे डेयरी आय अधिक स्थिर हुई है। लातूर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को वर्मी-कम्पोस्ट और वैल्यू एडिशन का प्रशिक्षण दिया गया। खेत और घर के कचरे को नियमित आय के स्रोत में बदला गया। कई गांवों में महिलाओं की आय पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी।

समस्या सिर्फ संसाधनों की नहीं, सोच की भी है

कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि KVK मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी "एकतरफा संरचना" रही। विज्ञान प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचा, लेकिन खेत की समस्या शोध संस्थानों तक उसी गंभीरता से नहीं पहुंच पाई।

आज किसान सिर्फ बीज या उर्वरक की जानकारी नहीं चाहता। वह पूछता है : कम पानी में खेती कैसे करें? जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटें? बाजार में बेहतर दाम कैसे मिले? और AI, ड्रोन या प्रिसिजन फार्मिंग जैसी तकनीकें उसके काम कैसे आएंगी? लेकिन कई KVK अब भी पुराने प्रदर्शन मॉडल और पारंपरिक प्रशिक्षणों तक सीमित दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कई किसान अब सलाह के लिए निजी इनपुट डीलरों, यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया समूहों पर अधिक निर्भर होने लगे हैं।

हिमाचल प्रदेश : पहाड़ों में तकनीक की खेती

हिमाचल प्रदेश के मंडी, सोलन और किन्नौर जैसे जिलों में KVK ने संरक्षित खेती (Protected Cultivation), ऑफ-सीजन स जी उत्पादन और हाई-डेंसिटी बागवानी को नई दिशा दी। पॉलीहाउस मॉडल ने छोटे किसानों को सीमित जमीन पर भी बेहतर आय का अवसर दिया। KVK मंडी द्वारा विकसित "फ्रूट फ्लाई ट्रैप" तकनीक से बागवानों को फल मक्खी की समस्या से राहत मिली, जबकि किन्नौर में मशरूम और सेब आधारित मॉडल ने युवाओं को खेती की ओर वापस आकर्षित किया।

हरियाणा : प्राकृतिक खेती की प्रयोगशाला

हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद जैसे जिलों में KVK किसानों को जीवामृत, बीजामृत और कम लागत वाली खेती के मॉडल सिखा रहे हैं। कई किसान रासायनिक लागत घटाकर मिश्रित खेती और देसी पशुपालन की ओर लौट रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इन प्रयोगों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या इन्हें छोटे प्रदर्शन प्लॉट से आगे बड़े स्तर तक ले जाया जा सकेगा।

पंजाब : पराली संकट और नई चुनौती

हरित क्रांति का केंद्र रहा पंजाब अब नई चुनौतियों से जूझ रहा है—पराली प्रबंधन, मिट्टी की गिरती गुणवत्ता और भूजल संकट। हाल के वर्षों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए KVK, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य एजेंसियों ने मिलकर जागरूकता अभियान, हैप्पी सीडर मशीन और बायो-डीकंपोजर तकनीक को बढ़ावा दिया। कई गांवों में सकारात्मक परिणाम भी मिले। लेकिन वास्तविकता अब भी जटिल है। समय की कमी, मशीनरी की लागत और धान-गेहूं चक्र की मजबूरी के कारण किसान पूरी तरह बदलाव नहीं अपना पा रहे। यही वह जगह है जहां KVK की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है—सिर्फ तकनीक बताने में नहीं, बल्कि व्यवहारिक समाधान देने में।

उत्तर प्रदेश : सबसे बड़ा नेटवर्क, लेकिन असमान असर

उत्तर प्रदेश में KVK का नेटवर्क देश में सबसे बड़ा है। कई जिलों में मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पोषण वाटिका और दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमों ने किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाई है। लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई इलाकों में किसान अब भी KVK से अपेक्षित जुड़ाव महसूस नहीं करते। स्टाफ की कमी, सीमित फील्ड विजिट और पुराने प्रशिक्षण मॉडल इसकी बड़ी वजहें हैं।

उत्तराखंड और दक्षिण भारत: छोटे मॉडल, बड़ा असर

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में KVK ने जैविक खेती, मधुमक्खी पालन और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया। महिला समूहों द्वारा वैल्यू एडिशन मॉडल तैयार किए गए, जिससे स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंच मिली। दक्षिण भारत—विशेषकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु—में कुछ KVK ने एकीकृत खेती, मत्स्य पालन और किसान इन्क्यूबेशन मॉडल को सफल बनाया। केरल के त्रिशूर और कोझिकोड में भूमिहीन किसानों के लिए इन्क्यूबेशन सेंटरों ने यह दिखाया कि KVK सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता भी विकसित कर सकते हैं।

भारत में KVK
ताकत और चुनौतियां

दूसरी तस्वीर ज्यादा बड़ी है इन सफलताओं के बावजूद बड़ी संख्या में KVK गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। संसदीय समितियों ने कई केंद्रों में स्टाफ की भारी कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की ओर ध्यान दिलाया है। कई KVK किराए के भवनों से चल रहे हैं, जहां आधुनिक लैब, डिजिटल सुविधाएं और पर्याप्त फील्ड स्टाफ तक उपलब्ध नहीं है। बिहार के लखीसराय जैसे जिलों में वेतन असमानता और कम मनोबल जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। कई किसानों का कहना है कि वे अब KVK की तुलना में निजी कंपनियों या मोबाइल आधारित सलाह पर अधिक निर्भर हो गए हैं।

अब "डिजिटल KVK" की जरूरत

विशेषज्ञों का मानना है कि KVK को "डिजिटल-फर्स्ट" मॉडल अपनाना होगा। कल्पना कीजिए—अगर किसान मोबाइल पर ही रोग पहचान, मौसम चेतावनी, लाइव विशेषज्ञ सलाह, बाजार मूल्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके, तो KVK की उपयोगिता कितनी बढ़ सकती है। कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन यह अभी भी व्यापक और समन्वित स्तर पर नहीं पहुंच पाई है।

नई खेती, नई चुनौतियां

भारत की कृषि अब सिर्फ अधिक उत्पादन की लड़ाई नहीं लड़ रही। अब चुनौती है—जलवायु परिवर्तन, जल संकट, मिट्टी की गिरती गुणवत्ता और वैश्विक बाजार की अस्थिरता। AI, ड्रोन, प्रिसिजन फार्मिंग और डेटा आधारित कृषि तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में अगर KVK पुराने मॉडल पर चलते रहे, तो उनके अप्रासंगिक होने का खतरा वास्तविक है। किसानों को अब सिर्फ प्रशिक्षण नहीं चाहिए; उन्हें खेत की वास्तविक समस्याओं का त्वरित समाधान चाहिए।

पुनरुद्धार का रास्ता

विशेषज्ञों के अनुसार KVK सुधार की दिशा में कुछ बड़े कदम जरूरी हैं—प्रदर्शन आधारित फंडिंग, डिजिटल विस्तार सेवाएं, स्थानीय समस्याओं पर आधारित नवाचार, FPO और एग्री-स्टार्टअप के साथ साझेदारी, और पारंपरिक ज्ञान का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता का होगा। KVK को "प्रशिक्षण देने वाली संस्था" से आगे बढ़कर "किसान की समस्या हल करने वाली संस्था" बनना होगा।

अंतिम सवाल: क्या सोए हुए दिग्गज जागेंगे?

KVK कभी विज्ञान और किसानों के बीच सबसे मजबूत पुल माने जाते थे। आज यह पुल कई जगह कमजोर पड़ता दिखाई देता है। लेकिन जहां ये संस्थाएं सक्रिय, नवाचारी और किसान-केंद्रित हैं, वहां उन्होंने यह साबित किया है कि खेती में वास्तविक बदलाव संभव है। भारत की खेती अब सिर्फ अधिक उत्पादन की लड़ाई नहीं लड़ रही—यह टिकाऊपन, तकनीक और भरोसे की लड़ाई भी है। ऐसे समय में KVK सिर्फ सरकारी संस्थान नहीं, बल्कि खेत और विज्ञान के बीच आखिरी भरोसेमंद पुल हो सकते हैं।

सवाल यही है— क्या यह पुल समय रहते मजबूत किया जाएगा? या धीरे-धीरे जर्जर होकर टूटने लगेगा?

KVK अभी भी महत्वपूर्ण हैं—शायद पहले से ज्यादा। लेकिन अब उन्हें सिर्फ जिंदा नहीं, जागृत होना होगा।

“भविष्य की खेती सिर्फ पानी पर नहीं, पानी बचाने की क्षमता पर टिकेगी।”

मानसून से पहले तैयारी नहीं की तो बारिश भी कम पड़ सकती है

कभी बाढ़, कभी सूखा और कभी अनियमित बारिश—भारत की खेती अब मौसम की अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे समय में सवाल सिर्फ यह नहीं कि कितनी बारिश होगी, बल्कि यह है कि गिरने वाली हर बूंद को कितना बचाया जा सकेगा।

रफ्तार मीडिया || संवाददाता

मानसून आने वाला है। खेत तैयार हो रहे हैं, बीज खरीदे जा रहे हैं और किसान आसमान की ओर उम्मीद से देख रहा है। लेकिन बदलते जलवायु दौर में अब अच्छी खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं रह सकती। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता बन चुका है और सिंचाई का बड़ा हिस्सा अब भी भूमिगत जल पर टिका है। ऐसे में सवाल सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती की स्थिरता का भी है। भारत में अब सूखा सिर्फ वहां नहीं पड़ता जहां बारिश कम होती है। सूखा अब वहां भी पड़ता है, जहां बारिश होकर भी पानी नहीं बचता। मई की तपती दोपहर में बुंदेलखंड का किसान सूखे पड़े खेत को देख रहा है। पिछले साल बारिश कम हुई थी। जो पानी आया भी, वह कुछ दिनों में बहकर निकल गया। उधर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में एक किसान खेत के किनारे बने छोटे तालाब से ड्रिप सिंचाई कर रहा है। बारिश वहां भी कम हुई, लेकिन उसकी फसल बच गई। दोनों किसानों के बीच फर्क सिर्फ बारिश का नहीं था—फर्क था पानी बचाने की तैयारी का।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग : बारिश को जमीन में रोकने की कला

भारत में हर साल अरबों लीटर बारिश का पानी बहकर नदियों और समुद्र में चला जाता है। अगर उसका एक हिस्सा भी खेत और गांव स्तर पर संरक्षित हो जाए, तो सिंचाई और भूजल संकट दोनों में राहत मिल सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मूल सिद्धांत सरल है—जितना संभव हो, बारिश के पानी को रोकना और जमीन में उतारना। लेकिन इसका असर बेहद बड़ा हो सकता है। आज देश के कई हिस्सों में चेकडैम, खेत मेड़बंदी, सोख्ता गड्ढे, तालाब पुनर्जीवन और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी संरचनाओं को फिर से महत्व मिल रहा है।

राजस्थान : जहां पानी सिर्फ संसाधन नहीं, संस्कृति है

राजस्थान लंबे समय से जल संरक्षण का प्रतीक रहा है। अलवर जिले में जोहड़ और चेकडैम मॉडल ने सूखे गांवों में भूजल स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई गांवों में वर्षों से सूखी पड़ी जलधाराएं दोबारा जीवित हुईं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान का मॉडल सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि सामुदायिक भागीदारी की ताकत को भी दिखाता है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में आज भी कई किसान “एक-एक बूंद” को बचाने की परंपरागत तकनीकों का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि कम बारिश वाले इलाके भी अपेक्षाकृत बेहतर जल प्रबंधन कर पा रहे हैं।

गुजरात : चेकडैम और माइक्रो-इरिगेशन का मॉडल

अगर जल प्रबंधन की सफल कहानियों की बात हो, तो गुजरात का नाम जरूर आता है। सौराष्ट्र और कच्छ जैसे जल संकट वाले क्षेत्रों में पिछले दो दशकों में हजारों छोटे चेकडैम और recharge संरचनाएं बनाई गईं। इससे कई इलाकों में भूजल स्तर सुधरा और सिंचाई क्षेत्र बढ़ा। गुजरात ने माइक्रो-इरिगेशन को भी बड़े स्तर पर अपनाया। ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकों के जरिए कम पानी में अधिक उत्पादन का मॉडल तैयार हुआ। कपास, सब्जियों और बागवानी फसलों में इसका असर स्पष्ट दिखाई दिया। विशेषज्ञों के अनुसार, ‘गुजरात ने दिखाया कि जल संकट वाले राज्य भी बेहतर प्रबंधन से खेती को स्थिर बना सकते हैं।’

अब मानसून पहले जैसा नहीं रहा

भारत अब ‘कम बारिश’ के दौर में नहीं, बल्कि ‘अनिश्चित बारिश’ के दौर में प्रवेश कर चुका है। भारतीय खेती की रीढ़ मानसून है। लेकिन अब मानसून का व्यवहार तेजी से बदल रहा है। बारिश देर से आती है, कम दिनों में ज्यादा होती है और कई बार बेहद असमान रहती है। कहीं अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, तो कहीं लंबे सूखे का दौर। भारत की लगभग 60% खेती आज भी मानसून पर निर्भर है। लेकिन दूसरी तरफ भूजल पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई। आज देश में निकाले जाने वाले कुल भूजल का लगभग 85-87% हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता बन चुका है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भूजल recharge की तुलना में कहीं तेजी से निकाला जा रहा है। कई इलाकों में जलस्तर हर साल नीचे जा रहा है। यानी संकट सिर्फ बारिश की कमी का नहीं, बल्कि जल प्रबंधन की विफलता का भी है।

खेत तालाब खेत का अपना जल बैंक

अगर पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण भारत में किसी जल संरचना की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, तो वह है—खेत तालाब।

इसका मॉडल बेहद सरल है: बारिश के पानी को खेत के किनारे बने तालाब में जमा करें और जरूरत के समय सिंचाई में उपयोग करें। लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं रहता। विशेषज्ञों के अनुसार खेत तालाब भूजल recharge बढ़ाते हैं, मिट्टी की नमी बनाए रखते हैं, सूखे के समय सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, दूसरी फसल लेने की संभावना बढ़ाते हैं और बागवानी व सब्जी उत्पादन को भी संभव बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश: "खेत तालाब योजना" से बदलती तस्वीर

उत्तर प्रदेश में "खेत तालाब योजना" के तहत हजारों तालाब बनाए गए। बुंदेलखंड जैसे जल संकट वाले क्षेत्रों में इसका असर सबसे अधिक दिखाई दिया। जालौन, बांदा और चित्रकूट जैसे जिलों में कई किसानों ने बताया कि पहले जहां खरीफ के बाद खेत खाली रह जाते थे, अब वे रबी और सब्जी फसलें भी लेने लगे हैं। कुछ इलाकों में तालाबों को ड्रिप सिंचाई से जोड़ा गया, जिससे पानी की बचत और उत्पादन दोनों बढ़े।

महाराष्ट्र : तालाब से बदला फसल चक्र

मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेत तालाब खेती की "जीवनरेखा" बनते जा रहे हैं। पहले जहां किसान सिर्फ एक सीजन की खेती कर पाते थे, अब वे सब्जियां, फल और दूसरी नकदी फसलें भी उगाने लगे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि खेत तालाब सिर्फ पानी नहीं बचाते—वे किसान की जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ाते हैं।

फसल चयन भी जल प्रबंधन है

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का जल संकट सिर्फ सिंचाई तकनीक से हल नहीं होगा। खेती के पैटर्न में बदलाव भी जरूरी होगा। धान और गन्ने जैसी पानी-गहन फसलों ने कई राज्यों में भूजल पर भारी दबाव डाला है। पंजाब और हरियाणा में कई इलाकों में ट्यूबवेल पहले की तुलना में कहीं अधिक गहराई तक जाने लगे हैं। यही वजह है कि अब बाजरा,ज्वार, दालें और कम पानी वाली फसलें फिर चर्चा में हैं।

माइक्रो-इरिगेशन हर बूंद का हिसाब

भारत का सबसे बड़ा जल नुकसान सिंचाई पद्धति में होता है। आज भी देश के अधिकांश हिस्सों में पारंपरिक बाढ़ सिंचाई पद्धति का उपयोग होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ चला जाता है। इसके मुकाबले ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकें 30–50% तक पानी बचा सकती हैं, उर्वरक उपयोग घटा सकती हैं, और उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। इसीलिए केंद्र सरकार "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)" के तहत "Per Drop More Crop" मॉडल को बढ़ावा दे रही है।

इजराइल मॉडल और भारत की सीख

इजराइल दुनिया के उन देशों में है, जहां बेहद कम पानी के बावजूद आधुनिक सिंचाई तकनीकों के सहारे उच्च उत्पादकता हासिल की गई। भारत अब उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में माइक्रो-इरिगेशन तेजी से फैल रहा है। अंगूर, अनार, गन्ना, सब्जियां और बागवानी फसलें अब बड़े स्तर पर ड्रिप आधारित हो रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में 'पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीकें ही खेती की असली प्रतिस्पर्धात्मक ताकत बनेंगी।'

मिलेट्स की वापसी पानी बचाने वाली खेती

अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के बाद मोटे अनाजों की चर्चा सिर्फ पोषण तक सीमित नहीं रही। अब इन्हें जल प्रबंधन के नजरिए से भी देखा जा रहा है। बाजरा और ज्वार जैसी फसलें कम पानी में टिकती हैं, सूखा सहनशील हैं और छोटे किसानों के लिए कम जोखिम वाली खेती का विकल्प देती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, 'भविष्य की खेती सिर्फ ज्यादा उत्पादन नहीं, बल्कि कम पानी में स्थिर उत्पादन की खेती होगी।'

हिमाचल और उत्तराखंड पहाड़ों का जल मॉडल

पहाड़ी राज्यों में छोटे जल स्रोतों और पारंपरिक प्रणालियों को फिर महत्व दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में "कुहल" सिंचाई प्रणाली और उत्तराखंड में पारंपरिक जलधाराओं के संरक्षण पर काम हो रहा है। कई गांवों में समुदाय आधारित जल प्रबंधन मॉडल दोबारा सक्रिय हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थानीय जल प्रणालियों को बचाए बिना पर्वतीय खेती को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता।

जल संकट सिर्फ खेती का संकट नहीं

जल विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि भारत का जल संकट सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं रहेगा। यह आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आय और सामाजिक स्थिरता तीनों को प्रभावित कर सकता है। कई क्षेत्रों में भूजल गुणवत्ता भी तेजी से बिगड़ रही है। पंजाब में यूरेनियम, राजस्थान में फ्लोराइड और कई राज्यों में नाइट्रेट प्रदूषण गंभीर चिंता बनते जा रहे हैं। यानी अब सवाल सिर्फ "पानी की मात्रा" का नहीं, बल्कि "पानी की गुणवत्ता" का भी है।

नई सोच: पानी को "संसाधन" नहीं, "पूंजी" समझना होगा

भारतीय खेती लंबे समय तक पानी को "उपलब्ध संसाधन" मानती रही। लेकिन अब यह सोच तेजी से बदल रही है। विशेषज्ञ "वॉटर बजटिंग" और "फार्म वाटर प्लान" जैसे मॉडल की बात कर रहे हैं, जहां किसान पहले पानी का हिसाब तय करेगा, फिर फसल का। यानी भविष्य की खेती में सवाल यह नहीं होगा कि "कितना पानी चाहिए", बल्कि यह होगा कि "उपलब्ध पानी में कौन-सी खेती टिकाऊ है।"

अंतिम बात : अगली लड़ाई पानी की होगी

भारतीय खेती का भविष्य सिर्फ अच्छी बारिश पर निर्भर नहीं करेगा। असली सवाल यह होगा कि गिरने वाली बारिश को कितना बचाया गया। खेत तालाब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माइक्रो-इरिगेशन और सूखा प्रबंधन अब तकनीकी शब्द नहीं हैं—वे आने वाले समय की खेती का आधार बनते जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत की खेती का भविष्य इस बात से तय होगा कि देश ने कितनी बारिश पाई नहीं बल्कि कितनी बारिश बचाई।

हर मौसम में मुनाफा

गेंदा कैसे बन रहा है छोटे किसानों की भरोसेमंद 'कैश क्रॉप'

कभी सिर्फ पूजा और सजावट तक सीमित माना जाने वाला गेंदा अब किसानों के लिए तेज नकदी देने वाली फसल बन चुका है। शादी सीजन, धार्मिक आयोजनों, होटल उद्योग और फूल मंडियों में लगातार बढ़ती मांग ने इसे छोटे और मध्यम किसानों की पसंदीदा खेती बना दिया है। कम अवधि, आसान खेती और नियमित नकदी प्रवाह ने गेंदे को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई "फास्ट कैश क्रॉप" में बदल दिया है।

रफ्तार मीडिया || संवाददाता

भारतीय खेती तेजी से बदल रही है। पारंपरिक फसलों में बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच किसान अब ऐसी खेती की तलाश में है, जहां कम समय में बेहतर आय मिल सके। ऐसे दौर में गेंदा सिर्फ फूल नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ कृषि कारोबार बनकर सामने आया है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से बिहार तक, हजारों किसान अब गेंदे की खेती को अतिरिक्त नहीं, बल्कि स्थिर नकदी आय के स्रोत के रूप में देखने लगे हैं।

सुबह के पांच बजे हैं। दादर फ्लावर मार्केट- जिसे लोग "फूल गली" के नाम से भी जानते हैं-में हलचल शुरू हो चुकी है। ट्रकों और छोटे वाहनों से गेंदा, गुलाब और रजनीगंधा की बोरियां उतर रही हैं। कुछ फूल मंदिरों के लिए जाएंगे, कुछ शादी समारोहों में और कुछ मुंबई के बड़े होटल और इवेंट कारोबार तक पहुंचेंगे। इसी भीड़ के बीच पीले और नारंगी गेंदे की सबसे ज्यादा मांग दिखाई देती है। फूल व्यापारियों के मुताबिक, त्योहारों और शादी के मौसम में कई बार रात भर ट्रकों की आवाजाही बनी रहती है।

उधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किसान अपने खेत में तैयार फूलों की तुड़ाई कर रहा है। उसके लिए यह सिर्फ फूल नहीं, बल्कि रोज की नकदी है। भारत में गेंदा अब केवल सजावट का हिस्सा नहीं रहा। यह तेजी से किसानों की "दैनिक आय वाली फसल" (daily income crop) बनता जा रहा है।

क्यों आकर्षित हो रहे हैं किसान?

गेंदा खेती का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी तेज नकदी है। धान या गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों में जहां किसान को लंबा इंतजार करना पड़ता है, वहीं गेंदा अपेक्षाकृत कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देता है।

सामान्यत: रोपाई के लगभग 60-70 दिन बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद लगातार कई चरणों में फूल निकलते रहते हैं। यानी किसान को एक बार में नहीं, बल्कि लगातार आय मिलती रहती है। यही वजह है कि कई किसान अब पारंपरिक फसलों के साथ गेंदे को "कैश सपोर्ट क्रॉप" की तरह जोड़ रहे हैं। मौसम या बाजार में नुकसान होने की स्थिति में यह अतिरिक्त नकदी का सहारा देता है। विशेषज्ञों के अनुसार अच्छी प्रबंधन वाली खेती में एक एकड़ से 80-120 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कीमतें मौसम और मांग पर निर्भर करती हैं, लेकिन शादी और त्योहार सीजन में कई मंडियों में गेंदा ₹40-₹80 प्रति किलो तक बिक जाता है। सामान्य दिनों में भाव कम हो सकते हैं, फिर भी नियमित मांग के कारण यह किसानों को नकदी प्रवाह बनाए रखने में मदद करता है।

छोटा फूल, लेकिन बड़ा कारोबार

भारत में फ्लोरीकल्चर यानी फूलों की खेती पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। बढ़ता शहरीकरण, डेस्टिनेशन वेडिंग, धार्मिक आयोजन, होटल उद्योग और ऑनलाइन फ्लावर डिलीवरी कल्चर ने फूलों की मांग को नई ऊंचाई दी है। इन सबके बीच गेंदा सबसे ज्यादा उगाए जाने वाले फूलों में शामिल है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसकी मांग लगभग सालभर बनी रहती है। मंदिरों, घरों, सार्वजनिक आयोजनों और राजनीतिक कार्यक्रमों तक—हर जगह गेंदे का उपयोग दिखाई देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि खुले फूलों के बाज़ार में गेंदे की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। यही कारण है कि छोटे और सीमांत किसान भी इसे आसानी से अपनाने लगे हैं।

महाराष्ट्र : फूलों की अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र

महाराष्ट्र—विशेषकर पुणे, नासिक और सतारा क्षेत्र—आज गेंदा उत्पादन के बड़े केंद्र बन चुके हैं। यहां किसान सिर्फ स्थानीय मंडियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मुंबई और अन्य महानगरों की flower supply chain से जुड़े हुए हैं। नासिक के किसान रमेश शिंदे बताते हैं, "पहले सिर्फ प्याज और टमाटर उगाते थे। दाम गिरने पर पूरा हिसाब बिगड़ जाता था। अब खेत के एक हिस्से में गेंदा लगाने से रोज़ नकदी आती रहती है।" रमेश ने दो एकड़ क्षेत्र में अफ्रीकन गेंदा (African Marigold) की खेती शुरू की। शुरुआत में उन्होंने इसे प्रयोग के तौर पर लगाया था, लेकिन लगातार मांग और जल्दी भुगतान ने उन्हें इस खेती की ओर आकर्षित किया। आज वे शादी सीजन में सीधे फूल व्यापारियों को आपूर्ति करते हैं। कई किसान अब ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक अपना रहे हैं। इससे पानी की बचत के साथ फूलों की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है।

दक्षिण भारत में क्यों मजबूत है बाजार?

कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गेंदा सिर्फ कृषि फसल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। मंदिरों, धार्मिक आयोजनों और त्योहारों में इसकी भारी खपत होती है। बेंगलुरु और मैसूर की फूल मंडियों में रोज बड़ी मात्रा में गेंदा पहुंचता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण भारत में फ्लोरीकल्चर का सबसे मजबूत आधार "दैनिक उपभोग बाज़ार" है। यानी मांग सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रहती। यही कारण है कि यहां कई किसान फूलों की खेती को स्थिर और अपेक्षाकृत सुरक्षित आय मानते हैं।

उत्तर भारत में तेजी से बढ़ता रुझान

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत के कई हिस्सों में भी गेंदे की खेती तेजी से बढ़ रही है। खासकर छोटे किसान इसे कम जोखिम वाली नकदी फसल के रूप में देख रहे हैं। पूर्वांचल और बिहार के कई किसान धान-गेहूं चक्र के बीच खाली अवधि में गेंदे की खेती कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। स्थानीय शादी बाजार और धार्मिक आयोजनों के कारण मांग भी बनी रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार, गेंदा छोटे किसानों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती।"

नई किस्मों ने बदली खेती की तस्वीर

कुछ वर्ष पहले तक किसान स्थानीय किस्मों पर निर्भर रहते थे, जहां फूलों का आकार और गुणवत्ता एक समान नहीं होती थी। लेकिन अब हाइब्रिड किस्मों ने गेंदे की खेती को अधिक व्यावसायिक बना दिया है। अफ्रीकन मेरीगोल्ड (Tagetes erecta) और फ्रेंच मेरीगोल्ड (Tagetes patula) की किस्में बाजार में तेजी से लोकप्रिय हुई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित "पूसा नारंगी" और "पूसा बसंती" जैसी किस्मों ने भी किसानों को बेहतर उत्पादन और आकर्षक रंग दिए हैं।

नई किस्मों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें:

- फूलों का आकार बड़ा होता है
- रंग अधिक चमकीला होता है
- शेल्फ लाइफ यानी भंडारण अवधि बेहतर रहती है
- और ट्रांसपोर्ट के दौरान नुकसान कम होता है

इसी वजह से अब किसान सिर्फ स्थानीय मंडियों तक सीमित नहीं हैं। कई व्यापारी सीधे गांवों से फूल खरीदने लगे हैं।

तकनीक बदल रही है फूलों की खेती

फ्लोरीकल्चर अब पूरी तरह पारंपरिक खेती नहीं रह गई। आधुनिक तकनीकों ने इस क्षेत्र को तेजी से बदलना शुरू कर दिया है। ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत होती है और पौधों को नियंत्रित मात्रा में नमी मिलती है। मल्चिंग से खरपतवार कम होते हैं और मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है। कई किसान स्टैगर्ड प्लांटिंग (Staggered Planting) यानी 'क्रमबद्ध रोपण' तकनीक अपना रहे हैं, जिससे बाजार में लगातार फूल उपलब्ध कराए जा सकें। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में फूलों की खेती भी प्रिसिजन फार्मिंग (Precision Farming) का हिस्सा बन जाएगी, जहां उत्पादन पूरी तरह बाजार की मांग और समय के हिसाब से योजनाबद्ध होगा।

फूल से आगे अब वैल्यू एडिशन की बारी

गेंदा अब सिर्फ माला और सजावट तक सीमित नहीं रहा। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, नेचुरल डाई, पोल्ट्री फीड एडिटिव और एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गेंदे से निकाला जाने वाला "ल्यूटिन" (Lutein) फार्मास्युटिकल और न्यूट्रास्युटिकल उद्योग में उपयोग किया जाता है। आंखों के स्वास्थ्य से जुड़े कई सप्लीमेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है। कुछ निजी कंपनियां अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल पर भी काम कर रही हैं, जहां किसान विशेष किस्मों की खेती कर प्रोसेसिंग यूनिट्स को सीधे फूल उपलब्ध कराते हैं। यानी आने वाले समय में गेंदा सिर्फ फूल बाजार का हिस्सा नहीं रहेगा—यह प्रसंस्करण-आधारित कृषि और कृषि उद्योग से भी जुड़ सकता है।

फ्लोरीकल्चर : बदलती खेती की नई तस्वीर

भारत में फ्लोरीकल्चर अब लग्जरी फार्मिंग नहीं रह गई। यह धीरे-धीरे छोटे किसानों की व्यवहारिक खेती बनती जा रही है। बढ़ते शहरीकरण, इवेंट उद्योग, धार्मिक पर्यटन और ऑनलाइन डिलीवरी कल्चर ने फूलों की मांग को स्थायी रूप से बढ़ाया है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स और बड़े आयोजनों की बढ़ती संख्या ने भी फूलों की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारतीय फ्लोरीकल्चर सेक्टर और तेजी से विस्तार करेगा, खासकर उन किसानों के बीच जो कम क्षेत्र में ज्यादा मूल्य वाली खेती करना चाहते हैं।

चुनौतियां भी कम नहीं

फिर भी यह खेती पूरी तरह आसान नहीं है। मौसम का अचानक बदलना, भारी बारिश, फूल सड़न रोग और बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव किसानों के लिए बड़ी चुनौती बने रहते हैं। त्योहारों के बाद कई बार कीमतें तेजी से गिर जाती हैं। ऐसे में सही टाइमिंग और मार्केट लिंकेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फूलों की खेती में ट्रांसपोर्टेशन का नुकसान किसानों के लिए बड़ा मुद्दा हैं, क्योंकि फूल जल्दी खराब हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोल्ड-चेन और संगठित तौर पर 'फूलों की मार्केटिंग' मजबूत हो जाए, तो किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

खेतों में खिल रही है नई नकदी संस्कृति

भारतीय खेती अब सिर्फ अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहती। किसान ऐसी फसलों की ओर बढ़ रहा है, जहां कम समय में बेहतर मूल्य और लगातार नकदी मिल सके। गेंदा उसी बदलाव की कहानी है। यह सिर्फ खेतों में खिलने वाला फूल नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उभरती नई नकदी संस्कृति का प्रतीक बनता जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज भारतीय खेती में अब सिर्फ अनाज ही नहीं - रंग भी कमाई देने लगे हैं।

बाजरा, अरहर, सोयाबीन और मक्का सही चयन से 30–50% तक बढ़ सकती है आय

भारत में खरीफ सीजन (जून-अक्टूबर) किसानों के लिए अवसर और जोखिम दोनों लेकर आता है। बढ़ती लागत, अनिश्चित मानसून और बाजार की बदलती मांग के बीच अब केवल पारंपरिक खेती से काम नहीं चलता। अगर किसान सही फसल का चयन और मिश्रित खेती अपनाएं, तो वे प्रति एकड़ 30-50% तक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस लेख में हम चार ऐसी प्रमुख फसलों—बाजरा, अरहर (तूर), सोयाबीन और मक्का—का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कम लागत में बेहतर रिटर्न देने के लिए जानी जाती हैं।

बाजरा : कम पानी, कम लागत, बढ़ती मांग

1 बाजरा आज सिर्फ परंपरागत अनाज नहीं, बल्कि "सुपरफूड" बन चुका है। सूखा सहनशील होने के कारण यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है। इसके साथ ही यह कम पानी, कम लागत और कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी उपज देने की क्षमता रखता है, जिससे किसानों का जोखिम घटता है।

पोषण के लिहाज से भी बाजरा बेहद समृद्ध है—यह फाइबर, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं की पहली पसंद बना रहा है। बदलते जलवायु परिदृश्य में बाजरा न सिर्फ खेती को टिकाऊ बनाता है, बल्कि भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा का मजबूत आधार भी बन सकता है।

क्यों फायदेमंद?

- बहुत कम सिंचाई में भी अच्छी पैदावार
- गरीब मिट्टी में भी उगने की क्षमता
- कीट और रोगों का कम असर
- हेल्थ फूड के रूप में बढ़ती बाजार मांग

बाजरा: लागत बनाम रिटर्न

- उत्पादन: 6-10 क्विंटल/एकड़
- लागत: ₹6,000-₹10,000/एकड़
- MSP (लगभग): ₹2,500+/क्विंटल

अरहर (तूर): स्थिर आय + मिट्टी की सेहत

2 अरहर एक ऐसी फसल है जो न केवल आय देती है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है। दाल की स्थायी मांग के कारण इसकी कीमत अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। इसके पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके भूमि की गुणवत्ता सुधारते हैं, जिससे अगली फसलों को भी लाभ मिलता है। साथ ही, यह कम इनपुट में अच्छी उपज देने वाली फसल है, जो किसानों के लिए जोखिम कम और मुनाफा सुनिश्चित करने का बेहतर विकल्प बनती है।

क्यों फायदेमंद?

- नाइट्रोजन फिक्सेशन से मिट्टी सुधार
- कम खाद की जरूरत
- बाजार में स्थिर मांग

- अरहर: लागत बनाम रिटर्न
- उत्पादन: 4-6 क्विंटल/एकड़
- लागत: ₹8,000-₹12,000/एकड़
- MSP (लगभग): ₹7,000+/क्विंटल

ध्यान रखें : अरहर की अवधि लंबी (150-180 दिन) होती है, इसलिए इसे अक्सर इंटरक्रॉपिंग में उगाना ज्यादा फायदेमंद रहता है।

सोयाबीन : कम समय में "कैश क्रॉप"

3 सोयाबीन को "गोल्डन बीन" कहा जाता है क्योंकि यह कम समय में अच्छा मुनाफा देती है। तेल और पशु आहार उद्योग में इसकी भारी मांग है। इसके बीज में उच्च प्रोटीन और तेल की मात्रा होने के कारण यह बहुउपयोगी फसल मानी जाती है, जो खाद्य और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाती है। साथ ही, यह अपेक्षाकृत कम अवधि की फसल होने के कारण फसल चक्र में आसानी से फिट हो जाती है और किसानों को जल्दी नकदी उपलब्ध कराती है।

क्यों फायदेमंद?

- 90-110 दिन में तैयार
- अच्छी बाजार कीमत
- निर्यात और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मांग

सोयाबीन: लागत बनाम रिटर्न

- उत्पादन: 8-12 क्विंटल/एकड़
- लागत: ₹10,000-₹15,000/एकड़
- MSP (लगभग): ₹4,500+/क्विंटल

जोखिम : अधिक बारिश या जलभराव से नुकसान हो सकता है, इसलिए अच्छी ड्रेनेज जरूरी है।

खरीफ 2026 : मुनाफे वाली फसलों का स्मार्ट चयन

फसल	अवधि (दिन)	लागत	पानी	मुनाफा	जोखिम
बाजरा	70–90	बहुत कम	बहुत कम	अच्छा	बहुत कम
अरहर	150–180	मध्यम	कम	स्थिर	कम
सोयाबीन	90–110	मध्यम	मध्यम	उच्च	मध्यम
मक्का	80–100	मध्यम	मध्यम	उच्च	मध्यम

मक्का: बहुउपयोगी और हाई-डिमांड फसल

4 मक्का की मांग तेजी से बढ़ रही है—खासकर पोल्ट्री फीड, स्टार्च और बायोफ्यूल उद्योग में। इसकी बहुउपयोगिता इसे किसानों के लिए एक भरोसेमंद नकदी फसल बनाती है। यह कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है, जिससे जल्दी आय प्राप्त होती है और फसल चक्र में लचीलापन बना रहता है। साथ ही, उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक प्रबंधन से इसकी उत्पादकता में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है।

क्यों फायदेमंद?

- 80-100 दिन में तैयार
- मशीनों से खेती आसान
- कई उद्योगों में उपयोग

मक्का: लागत बनाम रिटर्न

- उत्पादन: 12-18 क्विंटल/एकड़
- लागत: ₹10,000-₹14,000/एकड़
- MSP (लगभग): ₹2,200+/क्विंटल

जोखिम: फॉल आर्मीवर्म जैसे कीट का खतरा—समय पर नियंत्रण जरूरी।

स्मार्ट किसान बनें, मुनाफा बढ़ाएं

आज का सफल किसान वही है जो सिर्फ खेती नहीं करता, बल्कि रणनीति के साथ खेती करता है—सही फसल चयन, मिश्रित खेती (Intercropping) और बाजार की समझ के साथ।

जोखिम कम और मुनाफा ज्यादा

महाराष्ट्र के लातूर जिले के किसान रमेश पाटिल ने पारंपरिक एकल फसल प्रणाली छोड़कर बाजरा + अरहर इंटरक्रॉपिंग अपनाई। पहले वे केवल एक फसल पर निर्भर रहते थे, जिससे मौसम की मार पड़ने पर पूरी आय प्रभावित हो जाती थी। लेकिन फसल विविधीकरण अपनाने के बाद उनकी खेती ज्यादा स्थिर और लाभकारी बन गई।

- पहले आय: ₹25,000/एकड़
- अब आय: ₹35,000–₹40,000/एकड़

इंटरक्रॉपिंग से उन्हें कई फायदे मिले—अरहर ने मिट्टी की उर्वरता सुधारी, जबकि बाजरा ने कम पानी में भी उत्पादन दिया। इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ा, बल्कि लागत भी नियंत्रित रही। बाजार में दोनों फसलों की अलग-अलग मांग होने से उन्हें बेहतर दाम भी मिलने लगे। उन्होंने बताया, "एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी संभाल लेती है—जोखिम कम और मुनाफा ज्यादा। अब खेती में भरोसा भी बढ़ा है और आमदनी भी।"

जोखिम और सावधानियां

- सोयाबीन: अधिक बारिश जलभराव नुकसान
- मक्का: कीट (Fall Armyworm) का खतरा
- अरहर: लंबी अवधि

मौसम जोखिम

- **बाजरा**: कम, लेकिन बाजार लिंक जरूरी

क्षेत्र अनुसार सही चयन

- महाराष्ट्र / राजस्थान: बाजरा + अरहर
- मध्य प्रदेश: सोयाबीन
- कर्नाटक / तेलंगाना: मक्का + अरहर

कम लागत + सही योजना = ज्यादा मुनाफा

और यही सोच आने वाले समय की खेती को परिभाषित करेगी, जहां किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि समझदार उद्यमी बनकर अपनी आय को लगातार बढ़ाएगा।

किसान के लिए सुझाव

- प्रमाणित बीजों का चयन करें
- मानसून के अनुसार समय पर बुवाई करें
- मिट्टी परीक्षण कराएं
- जैविक और संतुलित उर्वरक का उपयोग करें
- बाजार भाव देखकर ही बिक्री करें

इंतज़ार खत्म! 20–25 मई

बिहार की शाही लीची नज़ाकत में रानी, स्वाद में महारानी... एक फल नहीं, एक एहसास

रफ्तार मीडिया || संवाददाता

मई का महीना जैसे ही अपने रंग में आता है, उत्तर बिहार की धरती पर एक अलग-सी हलचल शुरू हो जाती है। बागों में लटके छोटे-छोटे गुच्छे धीरे-धीरे रंग बदलते हैं, और हवा में घुलने लगती है एक मीठी खुशबू—जो दूर से ही बता देती है कि शाही लीची का मौसम आ गया है। लेकिन यह सिर्फ एक फल के आने की खबर नहीं है। यह एक उत्सव है—मिट्टी, मौसम और मेहनत का। "नमस्कार! मैं हूं शाही लीची—नज़ाकत में रानी और स्वाद में महारानी। मेरी खुशबू में बसती है बिहार की मिट्टी की सौंधी महक, और मेरी हर बूंद मिठास में घुली होती है किसानों की मेहनत। मैं मुज़फ्फरपुर और वैशाली के उन बागों से आती हूं, जहां सुबह की ओस और दोपहर की धूप मिलकर मुझे आकार देती है। मैं सिर्फ एक फल नहीं हूं—मैं एक मौसम हूं, एक इंतज़ार हूं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, वैसे ही मेरा नाम हर ज़ुबान पर आ जाता है-'शाही लीची आ गई क्या?'मुझे सिर्फ खाया नहीं जाता, मुझे महसूस किया जाता है—हर दाने में रस, हर खुशबू में याद, और हर स्वाद में एक कहानी होती है। मैं आपकी थाली तक सिर्फ नहीं पहुंचती—मैं अपने साथ लाती हूं बिहार की पहचान, परंपरा और दिल से जुड़ा एक एहसास।"

2026 का सीजन: क्यों है खास?

तारीख याद रखिए : 20 से 25 मई 2026 यही वह समय है जब शाही लीची अपने पूरे शबाब पर होती है—हल्का गुलाबी-लाल रंग, पतला छिलका, रसीला गूदा और मिठास जो सीधे दिल में उतर जाए। लेकिन इस बार बात सिर्फ स्वाद की नहीं है - इस बार शाही लीची अपने साथ एक बेहतर मौसम, मजबूत फसल और नई उम्मीदों की कहानी भी लेकर आ रही है।

एक फल नहीं, एक पहचान

"नमस्कार! मैं हूं शाही लीची—नज़ाकत में रानी और स्वाद में महारानी। मेरी खुशबू में बसती है बिहार की मिट्टी की सौंधी महक, और मेरी हर बूंद मिठास में घुली होती है किसानों की मेहनत। मैं मुज़फ्फरपुर और वैशाली के उन बागों से आती हूं, जहां सुबह की ओस और दोपहर की धूप मिलकर मुझे आकार देती है। मैं सिर्फ एक फल नहीं हूं—मैं एक मौसम हूं, एक इंतज़ार हूं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, वैसे ही मेरा नाम हर ज़ुबान पर आ जाता है—'शाही लीची आ गई क्या?'

मुझे सिर्फ खाया नहीं जाता, मुझे महसूस किया जाता है—हर दाने में रस, हर खुशबू में याद, और हर स्वाद में एक कहानी होती है। मैं आपकी थाली तक सिर्फ नहीं पहुंचती—मैं अपने साथ लाती हूं बिहार की पहचान, परंपरा और दिल से जुड़ा एक एहसास।"

मौसम की कहानी: एक साल का फर्क, पूरी तस्वीर बदल गई

2025 का सीजन किसानों के लिए आसान नहीं था। मार्च-अप्रैल की असामान्य गर्मी, तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव और नमी की कमी ने फल के विकास को प्रभावित किया। कई बागों में गुठली का आकार बढ़ गया, पल्प कम हो गया और मिठास उम्मीद से कम रही। किसान की मेहनत थी, लेकिन मौसम साथ नहीं था। लेकिन 2026 में तस्वीर बदल गई है। इस बार प्रकृति जैसे किसानों के साथ खड़ी दिख रही है। संतुलित तापमान, अनुकूल आर्द्रता, और समय पर फूल और फल का विकास—इन सबने मिलकर लीची को उसका असली रूप दे दिया है। नतीजा साफ है: इस साल लीची का आकार बेहतर, रंग ज्यादा आकर्षक, और स्वाद कहीं अधिक मीठा और रसीला होने की उम्मीद है।

बिहार से दुनिया तक—शाही लीची की उड़ान

शाही लीची अब सिर्फ बिहार की नहीं रही—यह दुनिया की पहचान बन रही है। पहले से ही GI टैग मिलने के बाद इसकी विशिष्टता प्रमाणित हो चुकी है। अब 2026 में निर्यात को लेकर नई संभावनाएं खुल रही हैं। मध्य पूर्व और यूरोप में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। बेहतर कोल्ड-चेन और एयर-फ्रेट सुविधाओं के कारण अब ताजा लीची सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। यह सिर्फ बाजार नहीं बढ़ा रहा, यह किसानों की आय और आत्मविश्वास—दोनों को बढ़ा रहा है।

स्वाद के साथ सेहत—गर्मी का मीठा इलाज

शाही लीची सिर्फ स्वाद का आनंद नहीं देती, बल्कि शरीर को भी राहत देती है। विटामिन C से भरपूर यह फल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के लिए लाभकारी हैं और गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। यानी, यह सिर्फ एक फल नहीं—एक प्राकृतिक "समर कूलेंट" है।

किसान से आपकी थाली तक एक भावनात्मक यात्रा

जब आप एक लीची अपने हाथ में लेते हैं, तो वह सिर्फ एक फल नहीं होता। वह एक पूरी यात्रा होती है—खेत से बाजार तक, मौसम से मेहनत तक, और उम्मीद से स्वाद तक। वह किसान, जो तपती धूप में बाग की देखभाल करता है, जो हर मौसम की मार झेलता है, और हर फल में अपनी उम्मीद जोड़ता है—वही इस मिठास का असली निर्माता है।
हर लीची में छिपी होती है—मेहनत की कहानी, प्रकृति का संतुलन, और आपकी मुस्कान का वादा।

तैयार हो जाइए...

तो अब इंतज़ार खत्म होने वाला है। 20-25 मई के बीच शाही लीची आपके शहर, आपके बाजार और आपकी थाली में होगी। इस बार यह लेकर आ रही है—बेहतर स्वाद, अधिक मिठास, और शुद्ध बिहार की पहचान। अंतिम बात, इस साल की शाही लीची सिर्फ एक मौसमी फल नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है—प्रकृति, विज्ञान और किसान की साझी मेहनत की कहानी। इस मौसम का आनंद लें। स्थानीय किसानों का समर्थन करें और इस मिठास को सिर्फ चखें नहीं—महसूस करें। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिर्फ लीची नहीं—यह बिहार की आत्मा की मिठास है।

मीठी कहानी में एक कड़वा मोड़ भी...

लेकिन हर अच्छी फसल के साथ एक चुनौती भी आती है। इस बार बागों में फल छेदक कीट (Fruit Borer) चिंता का कारण बना हुआ है। यह कीट चुपचाप फल के अंदर प्रवेश करता है—बाहर से सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अंदर से फल खराब हो चुका होता है। यही वजह है कि किसान इस बार ज्यादा सजग हैं। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं—समय पर छिड़काव, नियमित निगरानी, और जैविक नियंत्रण उपाय। अच्छी बात यह है कि जागरूकता के साथ इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

RIMS
RAFTAAR INSTITUTE OF MEDIA STUDIES
RAFTAAR INSTITUTE
OF MEDIA STUDIES
Admission Started for Crash/Vocational
Course in Mass Communication
We Are Ready to Welcome You at
Raftaar Institute of Media Studies
Be Ready to Join
Course
100%
PLACEMENT
ASSISTANCE
Anchor
Reporter
Scriptwriter
Video Editor
Cameraman
Helpline Number
6203592707, 9334722857
UTTAM NIWAS, HARMU HOUSING COLONY
RANCHI- 02, JHARKHAND

रांची में चार दिन तक टूटते रहे एथलेटिक्स के रिकॉर्ड्स!

गुरविंदरवीर, विशाल टीके और तेजस्विन शंकर ने रचा इतिहास

राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में 22 से 25 मई 2026 तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गया. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, झारखंड सरकार के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और झारखंड एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से 750 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. चार दिन तक चले इस आयोजन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड, मीट रिकॉर्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन की झड़ी लग गई. ट्रैक से लेकर फील्ड इवेंट तक खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊंचाई दी. इस प्रतियोगिता के पहले दिन ही भारतीय स्प्रिंटिंग में नया इतिहास देखने को मिला. पुरुष 100 मीटर के सेमीफाइनल में ओडिशा के अनिमेष कुजूर ने 10.15 सेकेंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. स्टेडियम में मौजूद दर्शक इस प्रदर्शन के बाद उत्साह से झूम उठे. वहीं महिला लंबी कूद में एन्सी सोजन ने 6.75 मीटर की छलांग लगाकर नया मीट रिकॉर्ड अपने नाम किया.

पहले दिन महिला लंबी कूद, पुरुष और महिला 10 हजार मीटर दौड़, महिला डिस्कस थ्रो, पुरुष हैमर थ्रो तथा पुरुष और महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज के फाइनल मुकाबले आयोजित हुए. खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही संकेत दे दिया कि रांची में इस बार कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं. इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन पुरुष और महिला 100 मीटर, 400 मीटर, महिला ट्रिपल जंप, महिला शॉटपुट, महिला जेवलिन थ्रो, महिला 1500 मीटर और डेकाथलन सहित कुल 11 स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले हुए. इसी दिन पंजाब के गुरविंदरवीर सिंह ने पुरुष 100 मीटर फाइनल में 10.09 सेकेंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया. उन्होंने शुक्रवार के सेमीफाइनल में 10.17 सेकेंड दौड़ा था लेकिन फाइनल में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया. उन्होंने अनिमेष कुजूर के 10.18 सेकेंड के मीट रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. साथ ही ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए निर्धारित 10.16 सेकेंड के क्वालिफिकेशन मार्क को भी पार कर लिया. रेस के बाद गुरविंदरवीर सिंह ने कहा कि यह रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि उनके भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है. उनके कोच जेम्स हिलियर ने कहा कि खिलाड़ी लगातार अपने रेस प्लान को बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं और भविष्य में उनसे और बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है. हालांकि अनिमेष कुजूर फाइनल में 10.20 सेकेंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि रिलायंस के प्रणव प्रमोद 10.29 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इसी दिन पुरुष 400 मीटर दौड़ में तमिलनाडु के विशाल टीके ने इतिहास रच दिया. उन्होंने 44.98 सेकेंड का समय निकालकर भारतीय सरजमीं पर 45 सेकेंड से कम समय में 400 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बनने का गौरव हासिल किया. उन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड 45.12 सेकेंड बेहतर किया, जो पिछले वर्ष चेन्नई में बनाया गया था. विशाल टीके ने कहा कि उन्हें पहले से विश्वास था कि वह 45 सेकेंड की बाधा तोड़ देंगे. उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर विशेष तैयारी की थी. इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन भी बेहद ऐतिहासिक रहा. मध्य प्रदेश के देव मीणा और कुलदीप कुमार ने पुरुष पोल वॉल्ट में 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया.

29 गेंद, 97 रन, 12 छक्के: एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी

आया तूफान, टूटे कई सारे पूराने रिकॉर्ड

अपनी इस रिकॉर्ड पारी के साथ वैभव ने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल समेत कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. आइए उन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं. आईपीएल 2026 में वैभव अब तक 65 छक्के जड़ चुके हैं, जिसके साथ वो टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

म इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंद में 97 रन बनाकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. 15 साल के राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 12 छक्के जड़े. जिसकी वजह से राजस्थान न्यू चंदीगढ़ में 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. अपनी इस रिकॉर्ड पारी के साथ वैभव ने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल समेत कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. आइए उन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं. आईपीएल 2026 में वैभव अब तक 65 छक्के जड़ चुके हैं, जिसके साथ वो टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 2012 में आरसीबी के लिए खेलते हुए एक सीजन में 59 छक्के लगाए थे. वैभव इस सीजन में अब तक 680

रन बना चुके हैं, जो की एक आईपीएल सीजन में किसी भी अनकैप्ड द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. इससे पहले ये रिकॉर्ड राजस्थान के ही यशस्वी जायसवाल के नाम था. जिन्होने 2023 में कुल 625 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 97 रनों की पारी में 12 छक्के लगाए. जो कि आईपीएल के प्लेऑफ में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड है. इससे पहले प्लेऑफ में एक पारी के दौरान 10 छक्के लगाने का था. जो शुभमन गिल ने मुंबई के खिलाफ 2023 में किया था. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. जो कि आईपीएल प्लेऑफ में संयुक्त रूप से सबसे तेज फिफ्टी बन गई. इससे पहले ये रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम था जिन्होंने 2014 में पंजाब के खिलाफ 16 गेंद में फिफ्टी जड़ी थी.

रणवीर पर लगा बैन, आखिर क्यों FWICE ने 'धुरंधर' स्टार के खिलाफ अपनाया ये सख्त रवैया? जानें यहां

स फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज ने फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से रणवीर सिंह के अचानक बाहर निकलने के मामले में उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनाउंसमेंट किया कि 'डॉन 3' विवाद के चलते उन्होंने रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया है. सोमवार 25 मई को, मुख्य सलाहकार अशोक पंडित, अध्यक्ष बीरेंद्र नाथ तिवारी और मानद महासचिव अशोक दुबे ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज के इस फैसले के बारे में मीडिया को संबोधित किया. फेडरेशन के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने बताया कि फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन में रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इस दौरान रितेश सिधवानी खुद आकर उनसे मिले, जबकि फरहार अख्तर वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग में शामिल हुए. उन्होंने फेडरेशन को 'डॉन 3' से जुड़े मौजूदा विवाद और रणवीर के शूटिंग शुरू होने से ठीक तीन हफ्ते पहले ही प्रोजेक्ट छोड़ने के बारे में जानकारी दी. रणवीर को तीन बार खुद आकर मिलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

रणवीर को फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' में मुख्य भूमिका निभानी थी. लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शूटिंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही एक्टर ने फिल्म से बाहर होने का फैसला कर लिया. फरहान और उनके बिजनेस पार्टनर रितेश सिधवानी ने एक्टर के खिलाफ इंडस्ट्री की संस्थाओं में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई. हालांकि अब तक, न तो फरहान और न ही रणवीर ने इस विवाद के बारे में मीडिया से बात की है, और न ही दोनों में से किसी ने FWICE द्वारा रणवीर पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा को लेकर कोई बयान दिया है.

एक्टर ने उन्हें एक ईमेल भेजा

प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किया गया, तो एक्टर ने उन्हें एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. अशोक ने इस बात की भी पुष्टि की कि फरहान के प्रोडक्शन हाउस, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर से हर्जाने के तौर पर 45 करोड़ रुपये की मांग की है. अशोक पंडित के बाद, फेडरेशन के प्रेसिडेंट बी.एन. तिवारी ने मीडिया से बात की और बताया कि उन्होंने रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया है. वहीं, फेडरेशन के एक सदस्य ने कहा कि अब से, चाहे वह स्पॉट बॉय हो, डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो या लाइटमैन, कोई भी रणवीर के साथ काम नहीं करेगा.

SITE ADDRESS : BELLAHI , OPPOSITE GAYA AIRPORT GAYA (BIHAR)

raftaarhr@gmail.com

6203592707,8709733241,6203764769

7970599666

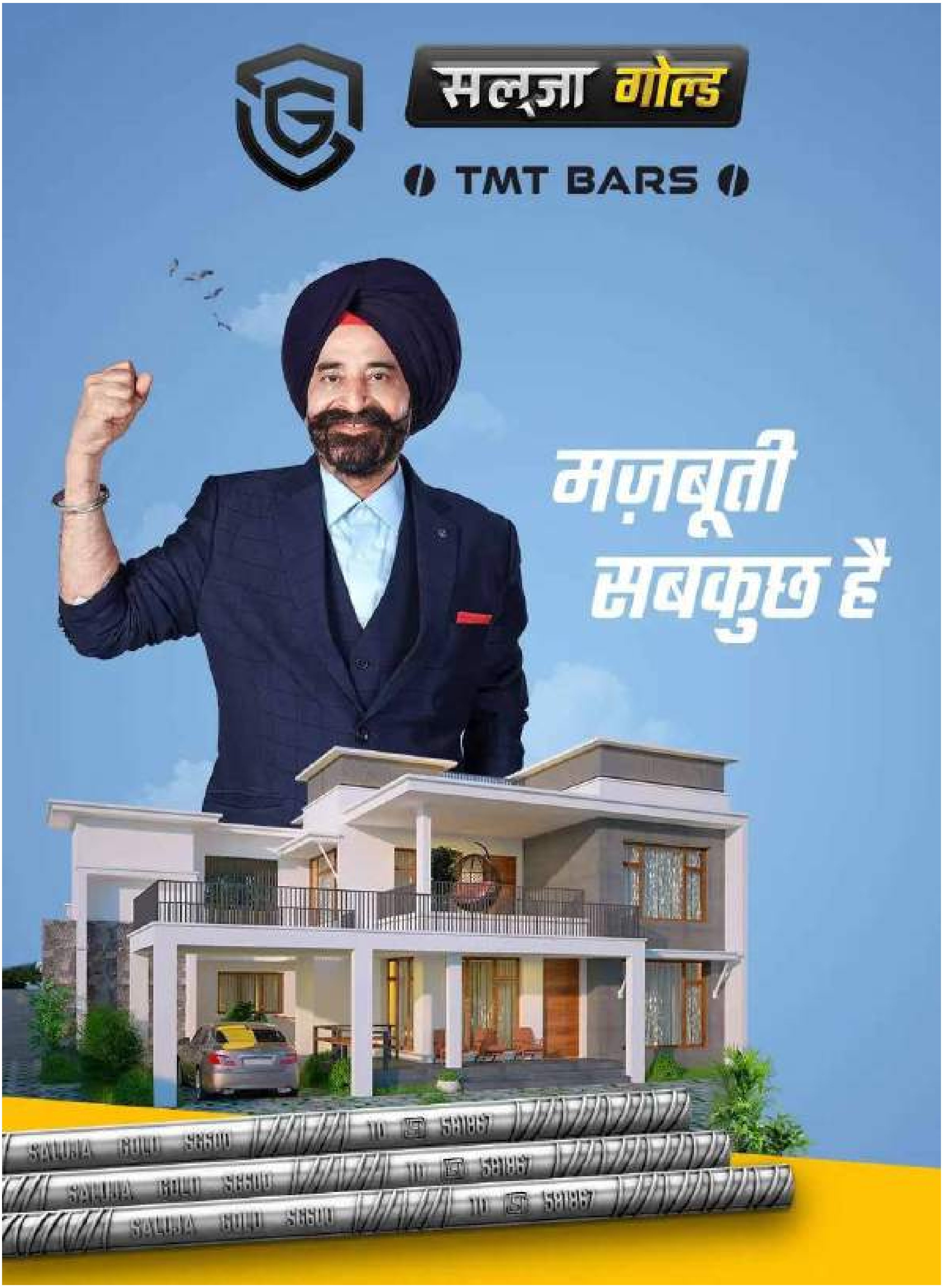
सलूजा गोल्ड
TMT BARS
मज़बूती
सबकुछ है